● वर्ष-4
● अंक-134
रायपुर, बुधवार
15 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» पहली मुलाकात में जानें एक-दूसरे को

दिल्ली के स्कूलों को धमकी का मामला, भाजपा का खुलासा

आप के साथ अफजल के संबंध

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के इस दावे पर आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा कि 12वीं कक्षा का एक छात्र, जिसे हाल ही में शहर के 400 से अधिक स्कूलों में बम की धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था, एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि एनजीओ ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में आवाज उठाई थी। हालाँकि, इसमें किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया। एक संवाददाता सम्मेलन में, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि आप के उन गैर सरकारी संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि आप के उन गैर सरकारी संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि आप के ऐसे गैर सरकारी संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। फरवरी

2015 में अफजल गुरु की बरसी पर टुकड़े-टुकड़े के नारे लगे और आप ने महीनों तक फाइल बंद रखी... इन एनजीओ के लोग कौन हैं और क्या इनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के माता-पिता दोनों ने अफजल गुरु की क्षमादान याचिका का समर्थन किया था।

दिल्ली पुलिस ने 400 से अधिक स्कूलों को भेजे गए फर्जी बम ईमेल की जांच करते हुए महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा किया है, जिससे छात्रों में व्यापक चिंता फैल गई और कक्षाएं बाधित हो गईं। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मधुप तिवारी ने 14 जनवरी को खुलासा किया कि व्यापक फोरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद इन ईमेल को भेजने वाले के रूप में एक बच्चे की पहचान की गई। पुलिस ने कहा कि जांच में वीपीएन के उपयोग के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने ईमेल की उत्पत्ति को छिपा दिया।

आप का पलटवार

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर स्कूली बच्चों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया एक छात्र गैर सरकारी संगठन से जुड़ा था और इसका कनेक्शन एक राजनीतिक दल से है। संजय सिंह ने कहा कि आप (बीजेपी) स्कूली बच्चों को मिल रही धमकियों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पहली धमकी मई 2024 में दी गई थी।

संजय सिंह ने कहा कि अब करीब 9 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है लेकिन बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वह अलग-अलग एनजीओ की कहानियां बता रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। 10 महीने तक कोई जांच नहीं हुई लेकिन अब चुनाव से 15 दिन पहले वे मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। गौरतलब है कि संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कुछ महीने पहले, दिल्ली भर के स्कूलों में बम की धमकी वाले कई कॉल और ईमेल प्राप्त हुए थे। इससे माता-पिता और दिल्ली के लोगों के बीच तनाव और भय का माहौल पैदा हो गया था। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस के इस दावे पर आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा कि 12वीं कक्षा का एक छात्र, जिसे हाल ही में शहर के 400 से अधिक स्कूलों में बम की धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था, एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि एनजीओ ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में आवाज उठाई थी। हालाँकि, इसमें किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया।

300 बेटियां परिणय सूत्र में बंधी
सीएम साय ने दिया आशीर्वाद

गरीब बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहारा मिल रहा

रायपुर। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के तातापानी महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 300 बेटियों का सामूहिक विवाह हुआ. छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विधि विधान से शादी संपन्न हुई. मुख्यमंत्री ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह के आयोजन से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहारा मिल रहा है।

कुसमी विकासखंड की दिव्यांग कन्या कुंती नगेशिया ने अपने विवाह पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति और दिव्यांगता के कारण विवाह संभव नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद और योजना की मदद से आज मेरा सपना साकार हुआ। अन्य नव दम्पत्तियों और उनके परिजनों ने भी इस आयोजन की सराहना की।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, अन्य जनप्रतिनिधि और हजारों नागरिक इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साबने। मुख्यमंत्री ने नवदम्पतियों को आपसी सम्मान और जिम्मेदारी से वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि तातापानी महोत्सव ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का दामन नई उम्मीदों और खुशियों से भर दिया है।

मकर संक्रांति पर शाह का अजब-गजब अंदाज

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने मंगलवार को पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति मनाई। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में शाह के जश्न की झलक दिखाई दी। इस दौरान शाह ने पतंग काटने के बाद बोले जाने वाला 'काय पोछे' प्रसिद्ध नारा भी लगाया। पटेल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमित शाह ने अहमदाबाद के शांतिनिकेतन सोसाइटी में स्थानीय लोगों के साथ मकर संक्रांति मनाई और सभी को खुशी के इस त्योहार की शुभकामनाएं दीं।

अब शरद पवार ने दे दिए एमवीए में फूट के संकेत

सिर्फ चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक का गठन : पवार

नईदिल्ली। महा विकास अघाड़ी के सहयोगियों के बीच संभावित दरार की ओर इशारा करते हुए, राकांपा (सपा) सुप्रीमो शरद पवार ने मंगलवार को संकेत दिया कि उद्धव की सेना की तरह, उनकी पार्टी भी आगामी मुंबई नागरिक चुनाव अकेले लड़ेगी। पवार ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का गठन केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के लिए किया गया था और नगरपालिका या राज्य चुनाव एक साथ लड़ने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी।

पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ, तो चर्चा केवल राष्ट्रीय मुद्दों और चुनावों के बारे में थी। स्थानीय निकाय चुनावों या राज्य चुनावों के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। हालाँकि, पवार ने यह भी कहा कि एमवीए घटकों के बीच एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि यह तय किया जा सके कि क्या पार्टियों को अकेले नागरिक चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए या गठबंधन में रहना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए।

शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर 8-10 दिन में बैठक कर फैसला लिया जाएगा कि हम साथ लड़ेंगे या अकेले। गठबंधन के भीतर हमारा संवाद है। पवार की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है कि वह प्रतिष्ठित बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित स्थानीय निकायों के चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना (यूबीटी) ने शनिवार को पुष्टि की कि पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। फैसले की घोषणा करते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि स्थानीय चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा।

प्रमुख समाचार

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी: सीएम पुष्कर सिंह

नईदिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि मकर संक्रांति से शुरू होने वाले शुभ चरण के दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। हालांकि, उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई और कहा कि इसकी घोषणा इस महीने के भीतर की जाएगी

क्योंकि कानून को जमीन पर लागू करने के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी त्योहार जो आज पूरे देश में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल या बिहू जैसे विभिन्न नामों से मनाया जा रहा है, उस शुभ चरण की शुरुआत का प्रतीक है जब सभी अच्छे काम किए जा सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का कार्यान्वयन भी एक शुभ बात है। यह इस माह उत्तरायणी के दौरान किया जाएगा। आगामी शहरी स्थानीय निकाय के मद्देनजर यहां कैंट क्षेत्र में आयोजित एक अभियान बैठक के मौके पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जमीनी स्तर पर कानून को लागू करने के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अपने अंतिम चरण में है। आपको जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। यूसीसी की शुरूआत 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले धामी द्वारा किया गया।

3.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

नईदिल्ली। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भारी भीड़ देखी गई है। मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के दौरान 3.50 करोड़ से अधिक भक्तों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। योगी ने एक्स पर लिखा कि आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुम्भ-2025, प्रयागराज में पावन

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पवित्र संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने वाले सभी पूज्य संतगणों, कल्पवासियों व श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन! प्रथम अमृत स्नान पर्व पर आज 3.50 करोड़ से अधिक पूज्य संतों/श्रद्धालुओं ने अविरल-निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। योगी ने आगे लिखा कि प्रथम अमृत स्नान पर्व के सकुशल संपन्न होने पर सनातन धर्म के आधार सभी पूज्य अखाड़ों, महाकुम्भ मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वच्छताकर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं धार्मिक संस्थाओं, नाविकों तथा महाकुम्भ से जुड़े केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी विभागों को हृदय से साधुवाद तथा प्रदेश वासियों को बधाई! पुण्य फलें, महाकुम्भ चलें।

केंद्र कर रही कर अधिकारों को लेकर धोखा : सिद्धारमैया

नईदिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने अधिकारी पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र ने 10 जनवरी को राज्य सरकारों को 1,73,030 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी किया। सिद्धारमैया की पोस्ट में कर्नाटक को दी गई 6,310 करोड़ रुपये की राशि पर असंतोष व्यक्त किया गया। उनके अनुसार यह

एनडीए सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ एक बड़ा धोखा था। उन्होंने पोस्ट की शुरुआत यह कहते हुए की कि उन्होंने जानबूझकर कुछ दिन इंतजार किया यह उम्मीद करते हुए कि कर्नाटक भाजपा के नेता कन्नडिगाओं के लिए बोलने का साहस जुटाएंगे। सिद्धारमैया ने सवाल किया कि राज्य के भाजपा नेता कर्नाटक के हितों की रक्षा करने के बजाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने में क्यों व्यस्त थे, जिन्हें उन्होंने विश्वासघात के लिए दोषी ठहराया था। उन्होंने कर्नाटक के आर्थिक योगदान और उसके बजट आवंटन के बीच स्पष्ट अंतर की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी का केवल 5 प्रतिशत होने और भारत की जीडीपी में 8.4 प्रतिशत का योगदान देने और 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जीएसटी वृद्धि में देश का नेतृत्व करने के बावजूद, राज्य की हिस्सेदारी स्थिर हो गई है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चल रहा काम: कानून मंत्री

नईदिल्ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर काम अच्छी गति से चल रहा है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वर्तमान में यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास है। राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी पत्रिका पांचजन्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मेघवाल ने न्यायालय के अधीन पूजा स्थल अधिनियम पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहता है, तो वह एक हलफनामा दाखिल करेगा जो राष्ट्रीय हित में होगा। वक्फ विधेयक पर एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और विधेयक लाई, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब विधेयक पेश किया गया तो मांग उठी कि इसे एक समिति के पास जाना चाहिए, इसलिए जेपीसी का गठन किया गया। बैठकें हो रही हैं, फील्ड विजिट भी हो चुकी है>

बारूदी सुरंग में विस्फोट, छह जवान जख्मी, अस्पताल में भर्ती

नईदिल्ली। मंगलवार को राजौरी जिले के नौशेरा में भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में नियंत्रण रेखा के पास एक आकस्मिक विस्फोट में भारतीय सेना के छह जवान घायल हो गए। यह घटना तब घटी जब एक नियमित गश्ती दल क्षेत्र से गुजरते समय अनजाने में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हो

गया। सैन्य सूत्रों के अनुसार, सैनिक एक संवेदनशील क्षेत्र में अपनी सामान्य गश्त कर रहे थे, तभी उनमें से एक ने गलती से एक खदान पर कदम रख दिया, जिससे विस्फोट हो गया। विस्फोट के परिणामस्वरूप सभी छह सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। सौभाग्य से, सैनिकों को लगी चोटें जीवन के लिए खतरा नहीं हैं, और उन सभी की हालत स्थिर बताई गई है। सैनिकों को आगे के इलाज के लिए तुरंत नजदीकी चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। जिस इलाके में यह घटना हुई वह एलओसी के नजदीक होने के कारण उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, जहां पहले भी कई झड़पें हो चुकी हैं। जबकि सीमा सुरक्षा उपायों के हिस्से के रूप में ऐसे क्षेत्रों में आमतौर पर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं।

दिल्ली में कांग्रेस के सामने शून्य से शुरुआत करने की चुनौती

कृष्णमोहन झा

केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इसी के साथ वहां चुनाव में किस्मत आजमाने की मंशा रखने वाले राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान में तेजी आ गई है। इन दलों में आम आदमी पार्टी और भाजपा सबसे आगे चल रहे हैं जबकि अतीत में 15 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इन दोनों दलों के मुकाबले बहुत पीछे दिखाई दे रही है। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सत्तारूढ आम आदमी पार्टी यह मानकर चल रही है कि दिल्ली की जनता तीसरी बार भी उसे ही सत्ता की चाबी सौंपने का मन बना चुकी है जबकि भाजपा को पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करने में बुरी तरह असफल रही आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मतदाताओं का अब मोह भंग चुका है और इन चुनावों में जनता उसे सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर देगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों ही दलों के कार्यकर्ता उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं, दोनों ही दलों का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है । दूसरी ओर अगर दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व खुद ही यह स्वीकार कर चुका है कि इन चुनावों में उसे शून्य से शुरुआत करनी है। जिस पार्टी के नेताओं का ही मनोबल इतना टूट चुका हो कि वे शून्य से शुरुआत करने की निराशा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त

करने में भी संकोच न करें उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मन:स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वैसे हकीकत भी यही है क्योंकि दिल्ली के पिछले दो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत का स्वाद चखने का अवसर नहीं मिला है इसलिए उसे शुरुआत तो शून्य से ही करना है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के 2013 में संपन्न चुनावों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लडा था उसके बाद संपन्न हुए दोनों विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने उसके साथ चुनाव समझौता करने से परहेज़ किया था जिसका खामियाजा कांग्रेस को इस तरह भुगतना पड़ा कि वह एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में विफल रही और अब भी जो आसार नजर आ रहे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि इन चुनावों में भी हताशा की स्थिति से उबरना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा।

दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस तरह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं वह इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों को भी पसंद नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बयान भी जारी कर दिया है। इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यह घोषणा भी कर दी है कि वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की चुनाव सभाओं में उनके साथ मंच भी साझा करेंगे। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक होते हुए भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष भी ऐसा धर्म संकट पैदा हो गया है कि वे दिल्ली में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में होने वाली चुनावी रैलियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में झिझक रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों से तो यही ध्वनि निकलती है कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है भले ही सत्ता की बागडोर भाजपा के पास आ जाए । शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भाजपा के इशारों पर चलने का आरोप लगाया है ।आम आदमी पार्टी की ओर से तो यह धमकी भी दी जा चुकी है कि अगर कांग्रेस का रवैया नहीं बदलता तो वह इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से कांग्रेस को बाहर निकालने की मांग करने से परहेज़ नहीं करेगी । इसमें दो राय नहीं हो सकती कि दिल्ली विधानसभा की जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है वहां वह त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति निर्मित करने के लिए जी-तोड़ कोशिश करेगी। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर किसके वोट काटने की रणनीति पर चल रही है। सीधी बात है कि वह जिस तरह आम आदमी पार्टी के ऊपर जनता से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा रही है उससे आम आदमी पार्टी को नुक़सान होना तय है लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद इस हकीकत से अवगत नहीं है कि वह आम आदमी पार्टी का जितना नुकसान करेगी वह उतना ही भाजपा का फायदा होगा क्योंकि दिल्ली के मतदाता अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस इन चुनावों में भी अपना खोलने में सफल नहीं हो पाएगी।आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज़ मतदाताओं के लिए भाजपा से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक है)

तुरतुरिया धाम मेला स्थल में अव्यवस्थाओं का अंबार

■ निर्देश के बाद भी नहीं हुए पूरे काम

बलौदाबाजार। मकर संक्रांति के अवसर पर तुरतुरिया धाम में तीन दिवसीय पौष पूर्णिमा मेले का आयोजन होता है।इस साल भी मेले का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना लेकर आने वाले भक्तों के बीच मां काली के संतान दात्री स्वरूप की पूजा का महत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन मेले के आयोजन के बावजूद, प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों की कमी और अव्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं।

मेले के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें मेले की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, जनसुविधाओं की उपलब्धता, और कंट्रोल रूम की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण आदेश शामिल थे। इसके अलावा, कलेक्टर ने इस क्षेत्र में स्थित बीएसएनएल के मोबाइल टॉवर को सक्रिय करने का भी निर्देश दिए थे, ताकि नेटवर्क की समस्या दूर हो।वहीं जिन जगहों पर खतरनाक खाई है वहां बेरिकेड्स लगाने की बात कही गई थी।लेकिन अफसोस ये है कि निर्देशों का पालन हुआ।जिसके कारण मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है।

तुरतुरिया धाम में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब है। मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन नेटवर्क की कमी के कारण वो अपने परिजनों को अपनी सूचना देने में असमर्थ हैं। बीएसएनएल मोबाइल टॉवर को सक्रिय करने के आदेश के बावजूद, नेटवर्क की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस कारण लोग बार-बार नेटवर्क से कट जाते हैं, जिससे उनकी असुविधा बढ़ रही है।

मेले में सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। कलेक्टर ने शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन इस आदेश के बावजूद मेले में सुरक्षा से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में, दतान और खैरा से आए श्रद्धालुओं के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद स्थिति को संभालने में पुलिस को दिक्कतें आईं।

मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तुरतुरिया धाम तक पहुंचने वाली मुख्य सड़कें उबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी हुई हैं। कई जगहों पर जलभराव होने के कारण श्रद्धालुओं को धूल और कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। इस जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे यात्रा करना और भी कठिन हो गया है।इसके अलावा, शौचालयों की भारी कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन शौचालयों की अपर्याप्त संख्या के कारण श्रद्धालु खुले में शौच करने को मजबूर हो रहे हैं। ये स्थिति ना केवल असुविधाजनक है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जोखिमपूर्ण है। प्रशासन को इस गंभीर मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई और असुविधा न हो।प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व = तुरतुरिया धाम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। ये स्थान राम वन गमन पथ का एक हिस्सा है और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास स्थित है, जहां उन्होंने तपस्या की थी। इसके अलावा, बालमदेही नदी का संगम और बारनवापारा अभ्यारण्य का निकट होना इसे एक अद्वितीय स्थल बनाता है। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और शांतिपूर्ण वातावरण को श्रद्धालु और पर्यटक समान रूप से सराहते हैं।

तुरतुरिया धाम के पास स्थित बारनवापारा अभयारण्य न केवल धार्मिक, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह अभ्यारण्य तेंदुआ, चीतल, जंगली भालू, नीलगाय और दूसरे पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, बल्कि प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थल है।

तुरतुरिया धाम मेला, जो हर साल एक धार्मिक उत्सव के रूप में आयोजित होता है, इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई कठिनाइयों का कारण बन रहा है। प्रशासन को जल्द ही कदम उठाकर सड़क सुधार, मोबाइल नेटवर्क की स्थिति में सुधार, शौचालयों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।अगर ये समस्याएं समय रहते हल नहीं होतीं, तो भविष्य में श्रद्धालुओं को और भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मेले का उद्देश्य धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है, लेकिन अगर प्रशासन इन बुनियादी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेगा, तो इसका असर श्रद्धालुओं के अनुभव पर पड़ेगा, जो इस धार्मिक स्थल की साख को भी प्रभावित कर सकता है।

नक्सलियों को झटका, सुरक्षाबलों के हाथ लगे 14 भरमार बंदूक

नक्सली साहित्य व अन्य डम्प सामग्री बरामद

कोंड़ागांव। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना पुंगारपाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर कोंड़ागांव की डीआरजी एवं बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम थाना पुंगारपाल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुदूर, दीपाकोड़ेनार, तुमड़ीवाल के आस-पास जंगल-पहाड़ी क्षेत्र की आंर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान ग्राम तुमड़ीवाल जंगल-पहाड़ी क्षेत्र का घेराबंदी कर सचिंग करने पर बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री व दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया है।

कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने बताया कि नक्सली किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे, जिसे विफल करते हुए कोंडागांव जिला रिजर्व पुलिस बल और बस्तर फाइटर के जवान मंगलवार को कुंदर तुमड़ीबाल के जंगल-पहाड़ों पर नक्सलियों द्वारा छिपाये गए भरमार बंदूक 14 नग, टिफिन बम 14 नग, कुकर बम 2 नग, रस्सा 1 बण्डल, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामदगी के साथ ही जवानों का अभी भी लगातार उसके आस-पास के इलाकों में गस्त-सर्चिंग अभियान जारी है।

स्टॉक मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मुख्य सरगना ने 42 लाख रुपये की ठगी की थी

बिलासपुर। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए लोगों को स्टॉक मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना चिरागजी ठाकोर को बिलासपुर रेंज साइबर थाना ने पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। उसने निवेश करने का झांसा देकर 42 लाख रुपये की ठगी की थी। फरार चल रहे दो आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए लोगों को स्टॉक मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देता था। इसके लिए फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों ने प्रीमियम बल्क डेटा वेबसाइट से डेटा खरीदकर लोगों को निशाना बनाया। धरमजयगढ़ के व्यवसायी आनंद अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत की थी उससे करीब 42 लाख रुपये की ठगी शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर की गई है। मामले की जांच के दौरान साइबर थाना टीम ने तकनीकी जानकारी और बैंक खातों की पड़ताल कर आरोपी की पहचान की। इसके बाद निरीक्षक विजय चौधरी के नेतृत्व में टीम गुजरात पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से पांच दिनों की मेहनत के बाद मुख्य आरोपी चिरागजी ठाकोर (21) महेसाणा, गुजरात निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वे प्रीमियम बल्क डेटा कंपनी से शेयर ट्रेडिंग करने वालों के मोबाइल नंबर खरीदते थे। इन नंबरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था- नए ट्रेडर्स के नंबर 10 रुपये प्रति नंबर, सक्रिय ट्रेडर्स के नंबर 5 रुपये प्रति नंबर तथा लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे लोगों के नंबर 1 रुपये प्रति नंबर। इन नंबरों पर कॉल कर लोगों को मुनाफा कमाने का झांसा देकर उनके बैंक खातों में पैसा जमा करवाया जाता था। ठगी की रकम को फर्जी बैंक खातों और सिम कार्ड के जरिए निकाल लिया जाता था। मामले के अन्य दो आरोपी मीतुल और गजेंद्र की तलाश जारी है।

16 से 19 तक रायपुर व कोरबा के बीच पैसेंजर रद्द

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत बैकुंठपुर-सिलियारी सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग हेतु रिलीविंग गर्डर की लांचिंग की जाएगी। इस कार्य के लिए 16, 17 एवं 18 जनवरी को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा इसके चलते 16 से 19 दिसंबर तक रायपुर से कोरबा तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

रद्द होने वाली गाडिंयां-

16 जनवरी को गाडी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी।

16 जनवरी को गाडी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू स्पेशल रद्द रहेगी।

16 जनवरी को गाडी संख्या 68733 गेवरा रोड- बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी।

16 एवं 17 जनवरी को गाडी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी।

17 जनवरी को गाडी संख्या 68727 बिलासपुर-रायपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी।

18 जनवरी को गाडी संख्या 58201 बिलासपुर-रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

18 जनवरी को गाडी संख्या 58207 रायपुर-जूनागढ़ रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

19 जनवरी को गाडी संख्या 58208 जूनागढ़- रायपुर रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

19 जनवरी को गाडी संख्या 58280 रायपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

इसके अलावा 16 जनवरी को गाड़ी संख्या 68861/68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी।

नए मेला स्थल में होगा राजिम कुंभ का भव्य आयोजन

■ राजिम कुंभ 12 से 26 फरवरी तक होगा आयोजित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में अगामी माह के 12 से 26 फरवरी तक त्रिवेणी संगम में राजिम कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। राजिम कुंभ के भव्य आयोजन नये मेला स्थल में होगा। इसके लिए जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है।

राजिम कुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में हुई बैठक में राजिम विधायक श्री रोहित साहू, बैठक में पूर्व सांसद श्री चंदूलाल साहू, पूर्व विधायक श्री संतोष उपाध्याय, रायपुर संभाग के आयुक्त श्री महादेव कावरे, गरियाबंद कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल सहित धमतरी, महासमुंद एवं रायपुर और गरियाबंद जिले के वरिष्ठ अधिकारी, उप संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग श्री प्रतापचंद पारख सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में बताया गया कि आगामी माह में होने वाले कुम्भ कल्प आयोजन लगभग 52 एकड़ क्षेत्र में फैले नया मेला स्थल में होगा। नया मेला स्थल में श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। राजिम कुंभ आयोजन स्थल में व्यवस्थित रूप से दुकानों और विभागीय स्टॉल के साथ-साथ मीना बाजार भी लगाए जाएंगे। यहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा हेलीपैड भी बनाया जाएगा।

बैठक में संभाग आयुक्त श्री कावरे ने बताया कि राजिम मेला 12 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। गंगा आरती स्थल से नए मेला स्थल तक नदी किनारे कनेक्टिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं के आने-जाने में आसानी होगी। इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही घाट निर्माण, मरम्मत एवं आसपास साफ सफाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पुराने स्थल में केवल संत समागम एवं गंगा आरती का आयोजन होगा। इसके अलावा सभी आयोजन एवं गतिविधियां नए मेला स्थल में आयोजित की जाएगी। पुराने स्थल पर कोई भी अस्थाई दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी अस्थाई दुकान नई जगह पर लगाई जाएगी। संभाग आयुक्त श्री कावरे ने नए स्थल पर लगने वाले मीना बाजार एवं पार्किंग स्थल के लिए टेंडर प्रक्रिया के लिए जरूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुकानों का आबंटन एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी। इसके लिए भी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरबा में बवाल के बाद एक्शन पुलिस ने दर्ज की 6 एफआईआर

कोरबा। जिले की कुछ महिलाओं ने शिकायत थी कि उन्होंने फलोरा माइक्रोफाइनेंस सहित अन्य से ऋण लिया है। इस दौरान कई रिकवरी एजेंट उन्हें घर आकर वसूली के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। इस मामले में शिकायत प्राप्त होने पर आज जिले में अलग-अलग थाने में माइक्रोफाइनेंस के रिकवरी एजेंटां के विरूद्ध छह एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस थाना कटघोरा, उरगा और करतला में प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना की गई। इसी तरह कटघोरा एसडीएम ने बताया कि वित्तीय अनियमितता के संबंध में लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों की जांच के संबंध में अनुविभाग कटघोरा, जिला- कोरबा में संचालित माइक्रोफाइनेंस कंपनी क्रमशः एलएनटी बैंक कटघोरा, अन्नपूर्णा बैंक दीपका, सीसस बैंक दीपका, नैफिस बैंक कटघोरा, स्पंदना बैंक के कार्यालय को दल-बल के साथ सील किया गया। स्पंदन बैंक नवागांव कटघोरा के एजेंट प्रताप रूद्र शरण पिता अमृतलाल धीवर, निवासी सरखों बैगापारा चौकी नैला के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं अवैध वसूली करते पाया गया।

प्रोफेसर पर हमले की साजिश मुख्य आरोपी भेजे गए जेल

दुर्ग। भिलाई-3 थाना क्षेत्र के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें प्रोबीर शर्मा और उसके सहयोगी धीरज वस्त्रकार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल, कोर्ट से आरोपियों को रिमांड नहीं मिली। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पुलिस आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा से दोनों आरोपियों के अलावा उन्हें पनाह देने वाले व्यक्ति टी. पवन कुमार को गिरफ्तार कर भिलाई लेकर पहुंची। सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि प्रोफेसर के विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करने की साजिश करने वाले मुख्य आरोपी मारपीट प्रोबिर शर्मा,शिवम मिश्रा और धीरज वस्त्रकार की पुलिस को लंबे समय से तलाश रही थी। उन पर 10- 10 हजार का इनाम भी घोषित किया था।इस बीच पुलिस को उनके आंध्रप्रदेश के काकीनाड़ा में छुपे होने की जानकारी मिली। दो दिन पहले सुराग मिलने पर पुलिस ने काकीनाड़ा से प्रोबीर और उसके सहयोगी धीरज वस्त्रकार गिरफ्तार किया गया।

कोरबा एडीएम बनकर महाकुंभ में लिया वीआईपी ट्रीटमेंट

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा से परिवार सहित प्रयागराज पहुंचे युवक को दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में पीड़ित ने खुद को कोरबा जिले का एडीएम विक्रम सिंह जायसवाल बताया। अस्पताल में अफसर समझकर वीआईपी ट्रीटमेन्ट दिया गया। वहीं कोरबा जिला प्रशासन ने विक्रम जायसवाल नाम का एडीएम होने से इनकार किया है। अधिवक्ता संघ ने भी पंजीकृत सदस्य होने से इनकार कर दिया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने विक्रम कुमार जायसवाल नाम का एडीएम होने से इनकार किया है। यूपी में खबर प्रकाशित होने के बाद मामला सामने आया है जिसके बाद प्रशासन मामले की जांच में जुटा है।

बलात्कार पीड़िताओं के मुआवजे के लिए बजट में प्रावधान

बिलासपुर। राज्य शासन ने बलात्कार पीड़िताओं के मुआवजे के लिए इस बार के बजट में 26.7 करोड़ रुपये का अंतरिम प्रावधान किया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पीएन भारत ने दी। याचिका पर अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सत्यभामा अवस्थी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार पीड़िताओं, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए मुआवजा योजना लागू की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य शासन इस असमंजस में था कि मुआवजा राशि का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। हालांकि, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अदालत को जानकारी दी कि मुआवजा योजना को लागू करने के लिए राज्य शासन को कई बार स्मरण पत्र भेजे गए, लेकिन बजट स्वीकृति में देरी हो रही थी।

बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी शॉर्ट सर्किट से आग

राजनांदगांव। गांधी चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में सोमवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, इस आगजनी में आवश्यक दस्तावेज जलकर खाक हो गए। रात को लगी आग पर सुबह काबू पाया जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा में बीती रात को अचानक बैंक के भीतर धुंआ उठने लगा। काफी देर बाद आग लगने की जानकारी सामने आई। सालभर पहले खुले ब्रांच में ग्राहकों की खासी तादाद है। आग लगने की खबर के बाद फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ब्रांच के भीतर आवश्यक दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बैंक में हुए नुकसान के संबंध में अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। बैंक मैनेजर और स्टॉफ से बसंतपुर थाना प्रभारी जानकारी हासिल कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी रेनू ने किया था फ्लोरा मैक्स का शुभारंभ

कोरबा। कोरबा में फ्लोरा मैक्स का शुभारंभ किसी और ने नहीं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की पत्नी कोरबा की पूर्व महापौर रेनू अग्रवाल ने किया था। जिस कुर्सी में पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की पत्नी रेनू अग्रवाल बैठी हुई नज़र आ रही हैं वह और कोई नहीं 100 करोड़ की ठगी करने वाले फ्लोरा मैक्स के सिटी सेंटर मॉल के ऑफिस की हैं, और रेनू अग्रवाल के बगल मे जो शख्स दिखाई दे रहा हैं ये फ्लोरा मैक्स का मुख्य आरोपी अखिलेश सिंह हैं, और साथ में ठगराज के कोर कमेटी के सभी महिला सदस्य हैं, जो अभी जेल में हैं।

एक दिन पहले तक नगर विधायक और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन की बैंक के कार्यक्रम की फोटो को फ्लोरा मैक्स के नाम से वायरल करने का हथकंडा अपना रहे थे। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के असली खेल से पर्दा उठ चुका है। कोरबा में फ्लोरा मैक्स पर पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का हाथ था। जय सिंह की सरपरस्ती में कोरबा में यह कम्पनी फली-फूली। हर कार्यक्रम में रेनू अग्रवाल जाती थीं, कम्पनी के मुख्य सरगना से मंत्री के परिवार की नजदीकी थी।जयसिंह अग्रवाल जांजगीर चंपा और बिलासपुर के प्रभारी मंत्री भी थे, यही वजह हैं की इन जिलों में भी तेजी से फ्लोरा मैक्स कंपनी ने अपना जाल बिछाया।

इस पूरे मामले में वर्तमान में हो रहे आंदोलन के पीछे की कहानी को समझने की जरूरत है, कंपनी का मुख्य सरगना सलाखों के पीछे हैं। छोटे एजेंट पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कांग्रेस इन ठगों को बचाना चाहती है, कांग्रेस पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है।

हाईटेंशन तार बने रहवासियों के लिए परेशानी

■ महिला की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

कोरिया। बैकुंठपुर नगर पालिका के वार्ड 6, 10 और 11 के रहवासी इन दिनों बिजली के हाईटेंशन तार से परेशान हैं। 11 केवी के बिजली तार 80 परिवारों के लिए जानलेवा खतरा बने हैं। तार की ऊंचाई कम होने के कारण इन परिवारों को अपनी जान का डर सता रहा है। साल 2020 में बिजली की तार के कारण एक महिला की मौत हो चुकी है।इसके बाद भी प्रशासन ने तारों की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाए।

वार्ड के निवासी अफताब अहमद ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आलम ये है कि लोग अपने घरों की छतों पर जाने से डरते हैं।क्योंकि हादसे की आशंका बनी रहती है।

स्थानीय आबिर अली ने कहा हाईटेंशन तार गिरने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। मैंने अपनी छत को मजबूरी में मोड़ दिया है। कई बार सीएम जन चौपाल में भी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।

रहवासी शबनम अल्ताफ ने कहा बारिश के दौरान छत पर जाना असुरक्षित हो गया है। पहले भी करंट से एक महिला की मौत हो चुकी है। उनके बच्चे अनाथ हो गए। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर तुरंत कदम उठाए।

स्थानीय लोगों के मुताबिक वार्ड में कई जगह खुली जगह है जहां बच्चे खेलते हैं।इन खुली जगहों के ऊपर से तार निकाला गया है।ऐसे में हादसों का डर बना रहता है। तार जगह-जगह से टूटे हुए हैं। हाल ही में तार गिरने से घर का हिस्सा जल गया। एक बंदर करंट लगने से मर गया।प्रशासन से गुजारिश है कि तारों को जल्द शिफ्ट किया जाए।वहीं बिजली विभाग के मुताबिक राशि के कारण शिफ्टिंग का काम नहीं हो सका है फंड आते ही शिफ्टिंग करा दी जाएगी।

सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजेश लकड़ा ने कहा शिफ्टिंग का काम डिमांड राशि न मिलने की वजह से रुका हुआ है।शिफ्टिंग के लिए भुगतान की आवश्यकता है।जैसे ही राशि मिलेगी, काम पूरा कर दिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी

बिलासपुर। उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ. सुधेश धनखड़ 15 जनवरी को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विश्वविद्यालय और हेलीपैड के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। उप-राष्ट्रपति सुबह 11:55 बजे नई दिल्ली स्थित अपने निवास से दिल्ली हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे। 12:15 बजे वे वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होकर दोपहर 2 बजे रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से 2:50 बजे बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पास के हेलीपैड पर उतरेंगे। उप-राष्ट्रपति दोपहर 3 बजे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वे विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान वे छात्रों को संबोधित करेंगे और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह समाप्त होने के बाद, उप-राष्ट्रपति शाम 4:05 बजे हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। 4:50 बजे वे रायपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रात 6:55 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरेंगे।

मकर संक्रांति पर सीएम साय ने किया शासकीय कैलेंडर का विमोचन

रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की फोटो के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर के मूलमंत्र को दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़वासियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाया गया है। विमोचन पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत उपस्थित रहे।

पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को मिलेगा 10 लाख की सहायता : साय

रायपुर। बलरामपुर प्रवास पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस लाइन स्थित हेलीपेड पर कुछ पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता देने और उनके नाम से पत्रकार भवन का निर्माण बीजापुर में कराने की घोषणा की। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कोर्ट के आदेशानुसार ही हमने आरक्षण लाए हैं और कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, अगर विधानसभा में विधेयक पारित नहीं होता तो आरक्षण नहीं मिलता। 33 जिलों में से 16 अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे, 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

राज्यपाल डेका से पैरा एशिया कप के गोल्ड मेडल विजेता झा ने सौजन्य भेंट की

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में पंजा कुश्ती में पैरा एशिया कप के गोल्ड मेडल विजेता श्रीमंत झा ने सौजन्य भेंट की। श्री झा ने गत नवम्बर माह में मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। झा का यह 49 वां अंतर्राष्ट्रीय मेडल है। वे आगामी माह नार्वे में होने वाले पैरा विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित हो चुके हैं। राज्यपाल श्री डेका ने श्री झा की उपलब्धियों की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्री झा को प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार रूपए का चेक भी प्रदान किया।

अग्रवाल महिला मंडल ने मकर संक्रांति पर बांटे गरीब बच्चों को तिल व मुर्रा लड्डू

रायपुर। संक्रांति के अवसर पर छत्तीसगढ़ अग्रवाल महिला संगठन रायपुर जिला इकाई की महिला मंडल के द्वारा अशोका रत्न के शिव, राधा कृष्ण मंदिर के सामने गरीब बच्चों, अशोक रत्न के कर्मचारियों के साथ ही आने-जाने वाले राहगीरों को करीब 50 किलो खिचड़ी, पोहा, पुलाव, तिल व मुर्रा लड्डू, मुंगफली पपड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संरक्षिका अनिता अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्षिका गंगा अग्रवाल, प्रचार प्रसार मंत्री ज्योति अग्रवाल, प्रदेश महा मंत्री निधि अग्रवाल, रायपुर जिला अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल, संतोष दानोदिया, निशा अग्रवाल, सीता अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, डॉ नेहा, उषा सराफ, पदमा अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, ममता अग्रवाल, सुचिता अग्रवाल उपस्थित थी।

निकाय चुनाव से पहले भाजपा का ऐलान, रिजर्व सीटों पर ओबीसी लड़ेगी चुनाव

अरुण साव ने कहा पिछड़े वर्ग का आरक्षण शून्य करने की साजिश कर रही थी कांग्रेस

रायपुर। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में सियासी दंगल तेज हो गया है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर वार पर पलटवार जारी है। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में पीसी आयोजित की गई। प्रेस कांफ्रेंस में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर पार्टी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ किया कि बीजेपी आरक्षित सीटों पर ओबीसी को चुनाव लड़ाएगी। डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव कानून प्रेस कांफ्रेंस में कानून की किताब लेकर पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून के मुताबिक जो प्रावधान हैं उनके तहत हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह भ्रम और झूठ का जाल नहीं फैला रहे हैं।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने आरक्षण पर मचे बवाल का जवाब भी मीडिया के जरिए

कांग्रेस पार्टी को दिया। प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष किरण सिंह देव तीन ओबीसी मंत्रियों के साथ पहुंचे थे। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा भी प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनाव के आरक्षण के तहत एक भी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिला है। कांग्रेस बेवजह का मुद्दा बना रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि 33 जिले में से छत्तीसगढ़ के 16 जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत यह सभी जगह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आबादी के हिसाब से चार जगह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है।

अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास झूठ बोलने का रहा है। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। विरोध करने की रही है। काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। उस आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कभी विचार ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब मंडल आयोग का गठन हुआ था। जिसमें पिछड़े वर्ग आरक्षण देने के लिए पर उस आयोग की कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने कभी देखा तक नहीं।

अरूण साव ने कहा कि साल 1990 में जब वीपी सिंह की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तब उन्होंने जमकर विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की उन्हें धोखा देने के लिए अपने ही व्यक्ति को उच्च न्यायालय भेजा स्टे हुआ, और उस व्यक्ति को कांग्रेस ने पद से नवाजा।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जिस तरीके से विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य राज्यों की तुलना में आयोग का गठन करके संवैधानिक बाध्यता को पूरा करते हुए पिछड़ा वर्ग को सर्वाधिक आरक्षण देने का काम किया है।

प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव नेकहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर भाजपा किसी तरह की हानि नहीं होने देगी। बल्कि हम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ और हमारी जो आंतरिक व्यवस्था है हमने जितना हो सकता है, उतना आरक्षण दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को कहीं भी हानि नहीं पहुंचने दिया जाएगा।

ओबीसी आरक्षण में कटौती का विरोध, कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन

पीसीसी चीफ बैज बोले- चुनाव में ओबीसी वर्ग की जानता सरकार को देगी मुंहतोड़ जवाब

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इसका ऐलान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया। उन्होंने कहा, ओबीसी आरक्षण के विरोध में 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

कांग्रेस का कहना है कि पहले प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी। अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में साजिश कर ओबीसी आरक्षण में कटौती की है। अधिकांश जिला, जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है।

कांग्रेस ने कहा, मैदानी क्षेत्रों में अनेकों पंचायतें ऐसी है, जहां लगभग 90 से 99 प्रतिशत आबादी ओबीसी की है, लेकिन वहां पर भी ओबीसी के लिए सरपंच पद आरक्षित नहीं है। पंचों का आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में कम है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब

सामान्य घोषित हो चुकी है।

बीजेपी की प्रेसवार्ता पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए सरकार पर ओबीसी वर्ग को गुमराह कर चुनाव लड़ने से वंचित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बस्तर के ओबीसी वर्ग द्वारा कल सीएम कार्यक्रम को बहिष्कार करने की भी बात कही। बैज ने कहा, अनारक्षित सीटों पर ओबीसी वर्ग को लड़ाने की बात कर सरकार क्या एहसान कर रही है। ओबीसी एक जागरूक वर्ग है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बयान देकर गुमराह न करें। क्या उन्हें पता नहीं था कि इस आरक्षण से बस्तर से सरगुजा तक ओबीसी वर्ग को नुकसान हो रहा है।

बैज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने वाली सरकार के पास क्या कोर्ट जाने का विकल्प नहीं था। ये सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है इसलिए गुमराह करने वाली बात कर रही है। इतने नुकसान का आकलन सरकार ने नहीं किया था। कल सीएम की तीन सभा को ओबीसी समाज ने बहिष्कार कर दिया है। चक्काजाम धरना प्रदर्शन कर बस्तर बंद का ऐलान भी किया है। आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग की जानता इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी।

दिल्ली दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, एआईसीसी के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली जा रहे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाक़ात कर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कल तीन ज़िलाध्यक्षों की सूची आई है। जल्द ही पूरी तस्वीर साफ़ होगी।

फ्लोरामैक्स कंपनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई जयसिंह अग्रवाल की पत्नी रेणु अग्रवाल के तस्वीर मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी पूरी तरह से फंस चुकी है। बचाव के लिए तस्वीरें जारी कर रही। 15 साल की सरकार में मुख्यमंत्री ने भी चिटफ़ंड कंपनी का उद्घाटन किया है। कांग्रेस भी तस्वीरें जारी कर सकती है। मंत्री को डराने धमकाने की जगह मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में महिलाओं पर एफआईआर करना ग़लत है।

बीजेपी के पोस्टर वार पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सुरेश चंद्राकर के मुख्यमंत्री निवास जाने पर सवाल उठाते हुए बैज ने कहा, सुरेश चंद्राकर अरुण साव से मिलने क्यों गया था। क्या मोटा माल छोड़ने नहीं गया था। क्या उसके बीजेपी के नेताओं के साथ संबंध नहीं है ? सुरेश चंद्राकरग मुख्यमंत्री निवास क्यों गया था ? अब तक सूची क्यों नहीं सार्वजनिक नहीं की गई। पत्रकारों को डराने धमकाने की बीजेपी नेताओं की तस्वीरें है। बलरामपुर में पत्रकार के साथ हुई घटना का जवाब कौन देगा।

शिक्षा का मंदिर का नए भवन में विधिवत शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद रायपुर द्वारा एक और अनोखी पहल करते हुए दिव्यांग बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल - शिक्षा का मंदिर-नाम से आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया गया है । परिषद के अध्यक्ष एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान किए है। सप्रे शाला परिसर बूढ़ा पारा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद मुख्य कार्यालय के भू तल में इसे विधिवत पूजा पाठ करके शुरू किया गया है।

ज्ञात हो कि वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए बालगृह बालक माना कैम्प, बाल जीवन ज्योति बालिका गृह पुरानी बस्ती , बालिका गृह कोंडागांव के साथ स्पीच थेरेपी सेन्टर रायपुर का सफल संचालन कर रहा है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के साथ वोकेशनल ट्रैनिंग सेन्टर भी शुरू किया जा रहा है ताकि दिव्यांग

बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सक्षम बनाया जाए।

सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण , दीप प्रज्वलन , पूजा के साथ शिक्षा का मन्दिर प्री प्राइमरी स्कूल का विधिवत शुभारंभ के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉ अशोक त्रिपाठी, डॉ कमल वर्मा, महासचिव चंद्रेश शाह ने संबोधित किया, आभार प्रदर्शन संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम ने किया । इस अवसर पर कोषाध्यक्ष इंदिरा जैन, संयुक्त सचिव प्रकाश अग्रवाल, स्कूल प्रभारी संजीव बसन्त हुददार, छगन भाई पटेल, रत्ना पांडे, हर्षा जोशी,प्रभा सेंद्रे ,श्वेता सिंह, इंद्रसेन के साथ परिषद के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस संगठन में बदलाव के संकेत, बघेल और बैज दिल्ली तलब

रायपुर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का कभी भी बिगुल बज सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव की हलचल भी तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संगठन में बदलाव और मजबूती को लेकर दिल्ली में बड़ी तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली दरबार में तलब किया गया है।

सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में संगठन को लेकर बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं। मंगलवार दोपहर में दीपक बैज दिल्ली के लिए निकले हैं। आज ही देर शाम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली रवाना होंगे। छत्तीसगढ़

के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी सामान्य स्तर पर ऐसी समीक्षा करती रहती है। दोनों नेता दिल्ली जा रहे हैं संभव है त्रिस्तरीय चुनाव पर भी चर्चा हो। साल 2025 में पहली बार यह नेता दिल्ली जा रहे हैं तो नए साल की शुभकामना भी अपने बड़े नेताओं को देंगे।

माना जा रहा है कि भाजपा ने प्रदेश स्तर पर संगठन में जिस तरीके से बदलाव किए हैं, जिन राजनीतिक और जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के जिलों को मजबूत किया किया है। कांग्रेस उस रणनीति से परेशान है। कांग्रेस निकाय चुनावों में अपनी रणनीति को और मजबूत बनाने के लिए संगठन में बदलाव कर सकती है। संभव है इसपर दिल्ली में चर्चा हो।

कांग्रेस नेताओं के दिल्ली जाने के मामले पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ईटीवी भारत को बताया कि दीपक बैज दिल्ली जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्ययमंत्री भूपेश बघेल भी शाम को दिल्ली रवाना होंगे। संगठन की तैयारी और पार्टी के कामकाज की समीक्षा को लेकर पार्टी के नेता दिल्ली जाते रहते हैं।

अब एसडीएम और तहसील कार्यालय में भी हेलमेट अनिवार्य

रायपुर। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एसडीएम और तहसील कार्यालय में हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी और कर्मचारियों को हेलमेट लगाने के लिये निर्देशित किया गया है। वहीं जो अधिकारी और कर्मचारी बाइक से आ रहे हैं, वे हेलमेट और जो चारपहिया वाहनों से आ रहे हैं वो सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। ये फैसला कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्रास सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में लिया गया।

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज मंगलवार को कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्रास सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टोरेट कार्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 10 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहे। इसे सभी अनुविभाग और तहसील स्तर के कार्यालय में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि वाहन तय पार्किंग स्थल पर पार्किंग करें। सभी राजस्व अधिकारी अपने संबधित पुलिस थाने के अधिकारी से संपर्क रखें और दुर्घटना या किसी प्रकार हादसा होने पर तुरंत सूचना देकर जरूरी कार्रवाई भी करें। सभी तहसीलदार अपने कार्यालय में अनुशासन बनाए रखें और सभी लंबित प्रकरण का निपटारा करें। कलेक्टर सिंह ने कहा कि नगर निगम सहित जिले में परिवार सहायता पेंशन और निराश्रित पेंशन के प्रकरण अतिशीध्र निराकृत करें। यदि संबंधित बैंक में कोई दिक्कतें आती हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड का निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्कूली बच्चों का प्राथमिकता से बनाएं। एसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी सामूहिक रूप से प्रयास करें जो यातायात में बाधा पहुचाए उस पर कार्रवाई भी जाएगी।

मकान खाली कराने पहुंचा राजस्व अमला, तो परिवार ने की आत्मदाह करने की कोशिश

कहा- घर खाली कर अचानक कहां जाएंगे

रायपुर। राजधानी रायपुर में राजभवन के पास एक परिवार ने मकान खाली कराने प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मकान में बीते 10 साल से रहने वाले परिवार के मुखिया ने परिवार समेत आत्मदाह करने की कोशिश की है। परिवार को आत्मदाह करने से रोकने के लिए तत्काल पुलिस एक्शन में आई और समझा-बुझा कर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात हैं।

बता दें, राजस्व अमला कोर्ट के आदेश पर आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के उत्कल बस्ती इलाके में एक घर को खाली कराने पहुंचा था। इसी दौरान घर में रहने वाले दशरथ सोना और उसके परिवार ने काफी हंगामा किया।

दशरथ सोना ने बताया की हमारा घर हमसे जबरदस्ती छीना जा रहा है। हमारे

पिता जी ने घर को दस साल पहले लिया था। लेकिन आज जबरदस्ती, बिना सरकार के निर्देश के घर को पूरी बस्ती को बाल पूर्वक हटाया जा रहा है।

दशरथ सोना ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस तरह अचानक घर खाली कराने पर हम आनन-फानन में कहा जाएंगे? उसने आगे कहा कि जब घर ही नहीं रहेगा तो हमारे रहने का क्या मतलब है? इसलिए हम राजभवन के सामने ईक्षा मृत्यु के लिए पेट्रोल डालकर परिवार सहित अपनी जान देना चाहते हैं।

पीएससी नियुक्ति विवाद : भूपेश बघेल की बेटी की नियुक्ति की सीबीआई जांच की मांग

■ **मुख्यमंत्री को भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने सौंपा ज्ञापन**

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस शासन में हुए पीएससी घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण मांगे रखीं। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पूर्व की बेटी के पीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री उन्हें भरोसा दिलाया कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे।

ये हैं भाजपा नेता की मांगें

सन 2018 से लेकर 2023 तक आयोजित सभी परीक्षाओं एवं भर्तियों को सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाए।

2021 और 2022 की परीक्षा रद्द कर सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाए।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी के पीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

बता दें कि सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उनके भतीजे नीतेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके बेटे शशांक गोयल व बहू भूमिका कटियार, तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार किया है। सभी को कोर्ट में पेश कर 15 जनवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है।

बता दें कि टामन सिंह सोनवानी के भतीजे नीतेश सोनवानी का डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है। वहीं साहिल सोनवानी का डीएसपी के पोस्ट पर सलेक्शन हुआ है। इसके अलावा बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार दोनों का डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है।

ये है पूरा मामला

सीजीपीएससी 2019 से 2022 तक की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है। ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार-अनियमितता के आरोप में मामला दर्ज किया है। सीजीपीएससी ने 2020 में 175 पदों पर और 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली थी। प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया। इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों समेत कांग्रेसी नेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाई है।

बांग्लादेश कहीं दूसरा पाकिस्तान न बन जाए

शिवदान सिंह

वर्ष 1971 में जिस पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान से भारत ने मार भगाया था। 53 साल बाद फिर से पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में लौटने लगी है। इसका मुख्य कारण है काफी लंबे समय से पाकिस्तान की आईएसआई अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा वहां के युवाओं को शेख हसीना के विरुद्ध भड़का रही थी, क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखती थीं। इस कारण भारत की बांग्लादेश से लगती सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन पाकिस्तानी आईएसआई ने परोक्ष युद्ध के द्वारा भारत के लिए एक नया मोर्चा खोलकर उसकी सेना को बांग्लादेश की जमीनी और समुद्री सीमाओं पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील प्रदान कर दी है। इससे भारत के लिए युद्ध का एक तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया है। पिछले काफी समय से चीन भी बांग्लादेश में सक्रिय है। इसलिए इसमें चीन का भी पूरा सहयोग पाकिस्तान को प्राप्त हो रहा है। शेख हसीना के सोलह साल के शासनकाल में बांग्लादेश एक गरीब देश की श्रेणी से निकलकर प्रगतिशील देश की श्रेणी में आ चुका था, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं था। बांग्लादेश अब फिर कट्टरपंथ की राह पर है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके मुताबिक जनरल शमशाद मिर्जा खुद बांग्लादेश की सेना के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्फेंट्री और टैकटिस स्कूल, डिफेंस सर्विसेज कमांड स्कूल इत्यादि का दौरा करेंगे तथा वहां के स्टाफ कॉलेज में युवा अफसरों को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। पाकिस्तान के तत्कालीन शासक पूर्वी पाकिस्तान को एक गुलाम देश की तरह रखते थे, जिससे शेख मुजीब उर रहमान ने भारत की मदद से आजादी दिलवाई थी। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दोबारा अपने चंगुल में लेने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों का सहारा लिया। इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने जमाते इस्लामी की इकाई इस्लामी छात्र को भड़काकर उग्र प्रदर्शन करवाए और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान की इस हरकत में चीन ने उसे आर्थिक सहायता पहुंचाई, जिसके द्वारा जमाते इस्लामी अपना यह उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में चला रही थी। इस संगठन का उद्देश्य बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरह ही उग्रवादी सरकार स्थापित करना है। अब वह दिन दूर नहीं, जब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी मुस्लिम कट्टरपंथियों और उग्रवादियों के द्वारा चारों तरफ हिंसा का माहौल होगा और वह भी आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। दूसरी ओर, पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच में संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया चल रही है। परंतु भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन का धोखा देने का पुराना इतिहास रहा है। अभी पिछले काफी समय से चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारत के सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है और अपने इस मकसद को वह बांग्लादेश द्वारा पूरा करना चाहता है। इसलिए भारत को अब अपनी पूर्वी सीमाओं पर और भी ज्यादा चौकसी बरतने की जरूरत होगी। अब भारत को बांग्लादेश से इस प्रकार निपटना चाहिए, जिस प्रकार वह पाकिस्तान से निपट रहा है। इसको देखते हुए भारत को उसकी विकास योजनाओं से तब तक दूर रहना चाहिए, जब तक कि वह वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करता और पाकिस्तान तथा चीन के प्रभाव से अपने को अलग नहीं करता। खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश में प्रतिदिन हिंदुओं के पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है और उनकी स्त्रियों के साथ गलत किया जा रहा है। जबकि 1971 में भारत ने अपने 7,000 सैनिकों की बलि दी तथा अपनी एक पंचवर्षीय योजना का धन बांग्लादेश पर इसलिए खर्च किया था, ताकि बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण देश बन सके।

दिल्ली की जंग में मोदी और केजरीवाल

प्रभु चावला

एक किवदंती है कि आधुनिक दिल्ली को सात पुराने शहरों पर बनाया गया है। यद्यपि वैचारिक आधार पर देखें, तो यह सात से कहीं अधिक है, दिल्ली का एक ही चेहरा है- सत्ता। पांडवों से लेकर चौहानों तक, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, यह हमेशा सत्ता का केंद्र रही है। दिल्ली भारत का दिल और आत्मा है। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच चुनावी लड़ाई इसी आत्मा को हासिल करने की है। शहर एक बार फिर युद्ध के प्रतीकात्मक नगाड़ों-ढोल, पोस्टर, जुलूस, चुनाव प्रचार और प्रचार-प्रसार- का गवाह बन रहा है, ताकि 70 सदस्यीय विधानसभा पर प्रभुत्व जमाया जा सके। यहां एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं आक्रामक व तीखे मोदी और चतुराई में निपुण केजरीवाल, इनके बीच मौजूद है एक नेतृत्वहीन राज्य कांग्रेस, जो केवल आलोचना व तंज करने में खुश है।

दिल्ली आइसीयू में है। बीते कुछ वर्षों से, उपेक्षा, निराशा और जर्जरता ने इसकी सड़कों, सीवेज सिस्टम, अस्पतालों, पार्कों और खेल के मैदानों को चौपट कर दिया है। गंदगी के कारण यमुना घातक हो गयी है। अपराध बढ़ने से महिलाएं अंधेरे के बाद अकेले घर से निकलने में डरती हैं। शहर के लगभग तीन करोड़ (30 मिलियन) निवासी वर्ष में तीन महीने से अधिक समय तक विषैली हवा में सांस लेते हैं। यह विषाक्तता राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं की चुनावी शब्दावली को भी दूषित कर चुकी है। यह लड़ाई दो पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच है- भाजपा, जो केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए स्थानीय नेता की कमी महसूस कर रही है, उसे अपने सबसे बड़े नेता मोदी पर भरोसा करना पड़ा है।

भाजपा ने दिल्ली चुनाव को करो या मरो का मामला क्यों बना लिया है? आखिरकार, यह एक छोटा-सा राज्य है। केजरीवाल लगभग 30 मुख्यमंत्रियों में से एक थे। लगभग 130 अरब डॉलर की राज्य जीडीपी के साथ दिल्ली की जनसंख्या शायद ही राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। परंतु मोदी और उनके कमांडरों ने किसी भी कीमत पर दिल्ली पर कब्जा करने का निर्णय किया है। उन्होंने लगभग सभी नये दलबदलुओं के साथ-साथ

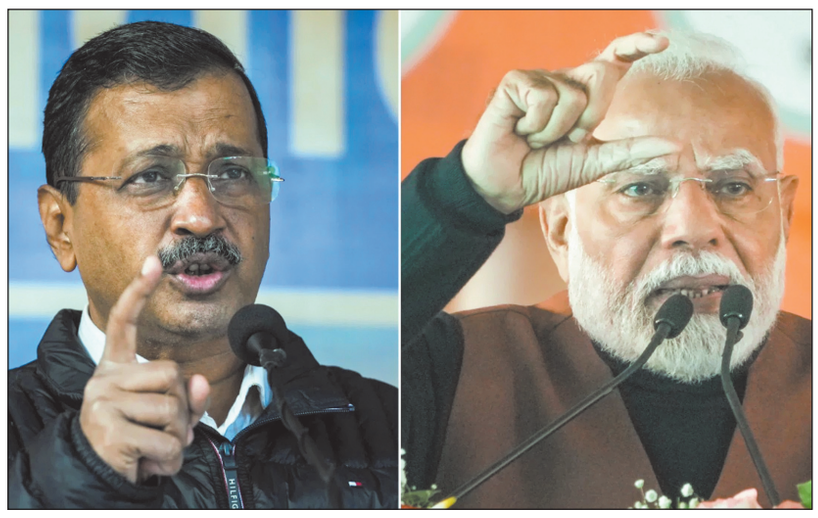

दिल्ली आइसीयू में है। बीते कुछ वर्षों से, उपेक्षा, निराशा और जर्जरता ने इसकी सड़कों, सीवेज सिस्टम, अस्पतालों, पार्कों और खेल के मैदानों को चौपट कर दिया है। गंदगी के कारण यमुना घातक हो गयी है। अपराध बढ़ने से महिलाएं अंधेरे के बाद अकेले घर से निकलने में डरती हैं।

अपने शीर्ष सांसदों को भी टिकट दिया है। सीएम चेहरे के अभाव में पार्टी ने दीवारों को मोदी की छवि से पाट दिया है। जाहिर है, भाजपा दिल्ली में भी डबल इंजन वाली सरकार चाहती है। भाजपा रायसीना हिल्स पर तो शासन करती है, पर वह 26 वर्षों से सिविल लाइंस सचिवालय से बाहर है।

केजरीवाल की हाइ-प्रोफाइल उपस्थिति भाजपा की राजनीतिक संभावना को खराब करती है। वह आगे चलकर भारत के सिंहासन के लिए एक दुर्जेय संभावित दावेदार हैं, क्योंकि वह सिंहासन भी दिल्ली में ही है। पर यदि देशव्यापी स्वीकार्यता और विश्वसनीयता की बात करें, तो केजरीवाल मोदी के लिए मामूली खतरा भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री के रूप में एक दशक से अधिक समय के बाद भी, मोदी की व्यक्तिगत रेटिंग 60 प्रतिशत से अधिक है, केजरीवाल की निचली दहाई अंक की तुलना में। मोदी ने बारंबार राष्ट्रीय चुनावों में इस बात को स्थापित किया है कि केजरीवाल दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकते।

वर्ष 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में, भगवा पार्टी ने राज्य की सभी सात सीटों पर जीत हासिल की। जबकि स्थानीय चुनावों में, मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बावजूद केजरीवाल ने भाजपा को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। असल में दिल्ली मॉडल का उपयोग करके भाजपा को नुकसान पहुंचाने की केजरीवाल की बढ़ती क्षमता भगवा ब्रिगेड को परेशान करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि केजरीवाल और मोदी दोनों ने एक ही समय में राष्ट्रीय परिदृश्य में कदम रखा। केजरीवाल जहां 2012 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के माध्यम से सुर्खियों में आये। वहीं मोदी 2013 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। जब मोदी देशभर में भ्रमण कर रहे थे, तब केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनायी और 2013 में 70 में से 28 विधायक सीटें जीतीं।

उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में अल्पकालिक सरकार बनायी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आप को मोदी लहर के सामने कोई अवसर नहीं मिला। पर मोदी को आश्चर्यचकित करते हुए एक वर्ष के भीतर ही 2015 में केजरीवाल ने भाजपा को नीचा दिखा दिया। तब से, केजरीवाल स्वयं को न केवल एक अपराजेय मुख्यमंत्री के रूप में, बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भी स्थापित करते आये हैं। उन्होंने गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार किया। आप ने 117 में से 92 सीटें जीत पंजाब पर कब्जा कर इतिहास रच दिया। बारह वर्षों के भीतर, यह उन पांच पार्टियों में से एक बन गयी है जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है।

चूंकि आप ने कई राज्यों में कांग्रेस को विस्थापित कर दिया है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस और राहुल गांधी की बजाय केजरीवाल के साथ बातचीत करना पसंद करती हैं। अब दिल्ली चुनाव के लिए, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। केजरीवाल ने प्राइम टाइम में बने रहने के लिए मीडिया का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। भाजपा प्रचार की इस प्रवृत्ति को हजम नहीं कर पायी है। इसके अतिरिक्त, केजरीवाल ने कभी भी मोदी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और उन्हें विषैले शब्दों के जरिये व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया। अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह उन्होंने शायद ही कभी मोदी को राजकीय समारोहों में आमंत्रित किया हो।

भाजपा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में देखती है। दिल्ली के किसी भी पिछले मुख्यमंत्रियों का कभी भी प्रधानमंत्री से सीधा टकराव नहीं हुआ। पर जैसे मोदी न तो वाजपेयी हैं और न ही नरसिम्हा राव, वैसे ही केजरीवाल भी कोई दीक्षित या मदन लाल खुराना नहीं हैं। कोई भी राजनीतिक स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी को उम्मीद है कि केजरीवाल की बहुप्रचारित आडंबरपूर्ण जीवनशैली के कारण उनकी स्वीकार्यता में कमी आयी है। उन्हें उम्मीद है कि उत्पाद शुल्क नीति में उनके कथित भ्रष्टाचार और मोदी पर अतिरंजित आक्रमणों से मतदाताओं का मोहभंग हो जायेगा। राजधानी में दो सम्राट नहीं हो सकते। मोदी की चुनौती तीन लोकसभा जीत के बाद लगातार तीसरी विधानसभा हार से बचने की है। राजधानी में, जहां शीतलहर आम बात है, क्या मोदी लहर केजरीवाल की तरंग-रोध पर विजय प्राप्त करेगी, यह इस सर्दी में दिल्ली की दुविधा है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

वास्तव में वोपदेव ने श्रीमद्भागवत पुराण की सूची तैयार की थी और भागवत का रहस्य प्रकट करने के लिए परमहंस नाम की टीका बनाई थी, तथा इसी सम्बन्ध में मुक्ताफल और हरिलीलामृत नामक ग्रन्थ भी लिखे थे। इस समय वह सूची छप चुकी है, मुरादाबाद से प्राप्य है तथा परमहंस प्रिया टीका भी मिलती है। इसलिये स्वामी जी का यह लेख चण्डूखाने की गप्प के बराबर है। श्रीमद्भागवत पुराण के कर्ता श्रीव्यास जी महाराज ही हैं।

(20) कुछ लोग यह भी आक्षेप किया करते हैं कि वेदव्यास जी का बनाया हुआ महाभारत प्रसाद-गुणयुक्त अनुष्टुप् श्लोकों में निबद्ध है और उसकी शैली वाल्मीकीय रामायण की तरह प्राय: आर्ष है, परन्तु श्रीमद्भागवत में आधुनिक कवियों जैसी उद्भट, सालङ्कार एवं लच्छेदार कविता का बाहुल्य है और प्रसंगानुसार अनेक बड़े 2 छन्दों का समावेश है। इससे भाषाविज्ञान के अनुसार भी इन दोनों ग्रन्थों का कर्ता एक नहीं हो सकता ।

(21) यह आक्षेप भी अत्यन्त कुतुहलजनक है। प्रतिवादी जिस भाषाविज्ञान के आश्रय से महाभारत और भागवत को भिन्न-कविनिर्मित सिद्ध करना चाहता है, प्राय: ऐसे ही हेतुओं को आगे रखकर पाश्चात्य पण्डित और रमेशचन्द्रदत्त आदि भारताय इतिहासकार वेदों को अनेक कर्ताओं की कृति सिद्ध करने की चेष्टा किया करते हैं।

कई समालोचक तो ऋग्वेद के ही प्रथम मण्डल और अन्यान्य मण्डल की भाषा में प्रबल अन्तर देख पाते हैं। कहना न होगा कि वेदों के सम्बन्ध में की गई उपर्युक्त आलोचनाओं का जो मूल्य आस्तिक-समाज में है, बही मूल्य पुराण महाभारतादि के विषय में भाषा-विभेद के आधार पर भिन्न कवि निर्माण की कल्पना का हो सकता है।

क्रमश: ...

भारतीय थल सेना दिवस

अभिनय आकाश

रूपहले पर्दे पर तो आपने अभिनेताओं को एक साथ दस-दस गुंडों की पिटाई करते या फिर दुश्मन देश के सैनिकों को मारते हुए खूब देगा होगा और इस पर तालियां भी खूब बजाई होंगी। लेकिन असल जिंदगी में आपको हीरो देखने हैं तो सीमाओं पर तैनात उन जवानों को देखिए जो रक्त को जमा देने वाली ठिठुरन में भी हमारी सीमाओं की रक्षा की खातिर जान हथेली पर लिए खड़े हैं। 15 जनवरी का दिन देश के बहादुरों को सलाम करने का दिन है। यूं तो साल के 365 दिन वह हमारी आजादी को बचाएं रखने के लिए संघर्ष करने वाली सेना को सलाम करने का दिन है। लेकिन ये एक ऐसा दिन है जब हमारी सेना अपनी आजादी का जश्न मनाती है। आज आपको बताते हैं कि आखिर 15

जनवरी को क्यों मनाया जाता है?

भारत में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। साल 1942 में पहले भारतीय सैन्य अफसरों को एक यूनिट कमांड करने का मौका मिला था। जबकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस ब्रूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस ब्रूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। केएम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। उसी समय से 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है।

इस दिन की शुरुआत इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने से होती है। इस मौके पर सेना के अत्याधुनिक हथियारों और टैंक-मिसाइल, जैसे साजो-सामान प्रदर्शित किए जाते हैं। इस दिन राजधानी दिल्ली और सेना के सभी छह मुख्यालयों में परेड आयोजित होती है। सेना अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है। सेना प्रमुख की तरफ से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जवानों और जंग के दौरान देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों की विधवाओं को सेना मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं।

भारतीय सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में से एक माना जाता है। गोलाबारूद-हथियारों के मामले में भारतीय सेना दुनिया में चौथे स्थाना पर आती है। भारतीय सेना के पास सटीक अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो इसे ताकतवर बनाती है। पूरे विश्व में भारतीय सेना एक मात्र ऐसी सेना है जो सिर्फ अपने दुश्मनों के हमले का जवाब देती है। भारतीय सेना के नाम कभी भी किसी देश पर पहले हमला न करने या उसे कब्जा करने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। भारतीय सेनासर्व-स्वयंसेवी बल है और इसमें देश के सक्रिय रक्षा कर्मियों का 80त्न से अधिक हिस्सा है। भारतीय सेना दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है, जिसके पास 12 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं।

भारतीय थल सेना का गठन ईस्ट इंडिया कम्पनी की सैन्य टुकड़ी के रूप में कोलकाता में 1776 में हुआ था, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना बनी और देश की आजादी के बाद इसे 'भारतीय थल सेना' नाम दिया गया।

ट्रंप का शपथग्रहण क्यों होगा खास?

अभिनय आकाश

रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास के बीच महीनों से जंग जारी है। कोविड महामारी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप्प पड़ी है। जाहिर है कि अमेरिका में नई सरकार को लेकर दुनिया को शांति और नए सिरे से कारोबार को मंदी से मुक्त होने की उम्मीद है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान दुनियाभर के वादे भी खूब किए थे। 20 जनवरी का दिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप का शपथग्रहण बहुत भव्य तरीके से हो रहा है जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। सभी को बुलाया गया, सभी जा रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से मीडिया में विमर्श का केंद्र ये रहा कि इसमें पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया। इसमें कुछ वर्ग को राष्ट्र का इतना अपमान दिखा कि वे पिछले 15 दिनों से दुखी नजर आ रहे हैं। आज बात ट्रंप के न्योतों पर करेंगे, तैयारियों पर करेंगे, किसने ट्रंप के निमंत्रण को बड़ी बेरुखी से ठुकरा दिया इस पर भी बात करेंगे।

अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, हंगरी से विक्टर ओरबन, इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा ट्रंप ने फ्रांस के विपक्षी नेता एरिक को भी न्यौता भेजा है। कई और पूर्व और वर्तमान शासनाध्यक्षों को भी ट्रंप ने शपथग्रहण में आमंत्रित किया है। लेकिन एक नाम ऐसा है, जिसे लोग ट्रंप की आमंत्रण सूची में लगातार तलाश रहे हैं। वो नाम नरेंद्र मोदी का है। कल से पहले तक ये सवाल लगातार किया जा रहा था कि मोदी ट्रंप के शपथग्रहण में शामिल होंगे या नहीं? मोदी-ट्रंप के रिश्ते जगजाहिर हैं।

ट्रंप के शपथग्रहण में मोदी को निमंत्रण नहीं मिलने को पिछले साल सितंबर की घटना से जोड़कर देखा जा रहा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क गए थे। उस समय ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। ट्रंप का मानना था कि मोदी के साथ एक हाई-प्रोफाइल मुलाकात से उनकी

चुनावी छवि को मजबूती मिलेगी। जब ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई, तो भारतीय राजनयिकों के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो गया. 2019 में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के दौरान ट्रम्प की अप्रत्यक्ष चुनावी बढ़त को कूटनीतिक गलती माना गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह तय किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से दूरी बनाए रखना भारत के दीर्घकालिक हित में होगा। ट्रंप इस बात से नाखुश थे कि मोदी से मुलाकात उन्हें चुनावी फायदा दिला सकता था, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया।

एस जयशंकर के अमेरिका दौरे पर निमंत्रण से जोड़कर देखा गया। यहां तक कहा गया कि पीएम मोदी ने न्यौता पाने के लिए ट्रंप के पास एस जयशंकर को भेजा। बीजेपी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुहासिनी हैदर का एक स्टेटस शेयर किया जिसमें जयशंकर के अमेरिका जाने की बात थी। इस पोस्ट को शेयर करते हुए स्वाम ने लिखा कि मोदी ने वेटर को अमेरिका भेजा है और उनसे कहा है कि वह उनके (मोदी) लिए निमंत्रण पत्र लेकर आए, अन्यथा वह अपनी नौकरी खो देंगे। जिसके बाद से एक वर्ग इस नैरेटिव को चलाने में लग गया कि ट्रंप के शपथग्रहण के लिए मोदी को नहीं बुलाया जा रहा है। ट्रंप मोदी से नाराज हैं।

वो ये भूल जाते हैं मोदी और ट्रंप की मुलाकात भले ही न हुई हो लेकिन अपने तमाम इंटरव्यू और भाषणों में वो दोनों के रिश्तों को जगजाहिर करते हुए बार बार दर्शाने की कोशिश की कि मोदी के साथ कितने अच्छे हैं। भारतवंशियोंं का ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में एकतरफा समर्थन भी मिला। ट्रंप का वो पॉडकास्ट भी खासा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मोदी को पिता सरीखा बताया था। ट्रंप मोदी की दोस्ती को सवाल उठाने वाले इस बात पर क्या कहेंगे कि जिनपिंग को शपथग्रहण के लिए क्यों निमंत्रण भेजा गया। जबकि दोनों के बीच के रिश्तें जगजाहिर हैं। और तो और बुलाए जाने के बावजूद भी जिनपिंग शपथग्रहण में नहीं जा रहे हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को होने वाले अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शपथग्रहण में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जयशंकर इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह न्योता अमेरिका की ट्रंप-वेंस शपथ ग्रहण कमिटी की ओर से भेजा गया है। अपने दौरे के दौरान जयशंकर ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों और वहां आने वाले कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बैठक करेंगे। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को अमेरिका पहुंचने की संभावना है, जिनमें कई देशों के प्रमुख भी शामिल हो सकते है। कुछ दिन पहले ही जयशंकर ने कहा था कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमारे द्विपक्षीय संबंध अच्छे रहे है। हालांकि, अलगाववादी गुरतपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर असहजता भी पैदा हुई है। एच-1बी वीजा को लेकर भी विवाद हो रहा है।

अब जब भारत को निमंत्रण मिल गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर के इसमें शामिल होने की बात भी सामने आने लगी तो एक वर्ग की तरफ से किया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से भारत को आधिकारिक रूप से आमंत्रित को किया है। लेकिन अपने दोस्त मोदी को पूछा भी नहीं। तो आपको ये भी बता दें कि संभवत: ये अमेरिका का पहला शपथग्रहण होगा जिसमें भारत को न्यौता मिला है। क्या आपको याद है कि कभी जवाहर लाल नेहरू या इंदिरा गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथग्रहण में बुलाया गया हो। जबकि वे बहुत बड़े नेता बताए जाते हैं। इतना ही नहीं कई विपक्षी नेता और ऐसे राजनेताओं को बुलाया गया है जो राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं हैं तो फिर राहुल गांधी को ही क्यों नहीं बुला लिया गया।

ट्रंप के करीबी कह रहे है कि राष्ट्रपति सभी देशो से खुलकर बात करना चाहते है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बहुत सारे रिश्तो को नई दिशा मिलेगी। बदले जियो पॉलिटिकल हालात फैसला करेंगे कि ट्रंप के इस कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के कितने करीबी संबंध कायम होगे।

अमेरिका के 248 सालों के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसा ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी तक करीब 170 मिलियन डॉलर का चंदा आ चुका है। नए प्रशासन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए कई बिजनेस टायकून और उद्योगपतियों ने ट्रंप की टीम को जी भर कर दान दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 170 मिलियन आ चुके हैं, जल्दी ही यह आंकड़ा 200 मिलियन डॉलर के पार पहुंच जाएगा। बोइंग, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई जैसे बड़े-बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने जमकर पैसा दान किया है। पोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शपथ ग्रहण में इतनी ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं कि मिलियन में दान करने वाले लोगों को भी वीआईपी टिकट देने से इनकार कर दिया गया है। ट्रंप की टीम के मुताबिक कई लोगों के वीआईपी पास देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि जगह की कमी है और सीटें पहले ही भर चुकी हैं।

आज का इतिहास

1943 दुनिया में सबसे अधिक क्षमता वाला कार्यालय भवन, संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है जिसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है।

1951 बुचेनवाल्ड के कमांडेंट और मजडनक एकाग्रता शिविरों की पत्नी, इल कोक को पश्चिम जर्मन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

1968 सिसिली में एक भूकंप ने 380 लोग मरे और करीब 1,000 लोग घायल हो गए।

1981 हिल स्ट्रीट ब्लूज़, अमेरिकी टेलीविजन के सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित शो में से एक, अपने पायलट एपिसोड, हिल स्ट्रीट स्टेशन को प्रसारित करता है।

1991 एलिजाबेथ द्वितीय, ऑस्ट्रेलिया की महारानी के रूप में, अपने स्वयं के ऑनर्स सिस्टम में अपने स्वयं के अलग विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार के लिए ऑस्ट्रेलिया को पहला राष्ट्रमंडल क्षेत्र बनने की अनुमति देने वाले पत्र पेटेंट पर हस्ताक्षर किए।

1993 सल्वाटोर द बीस्ट रीना, सिसिलियन माफिया के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक, तीन दशकों के बाद भगोड़े के रूप में गिरफ्तार किया गया था।

1995 दक्षिणी अलबामा और पश्चिमी वाशिंगटन क्रमश: नए क्षेत्र कोड 334 और 360 का उपयोग करना शुरू करते हैं।

1998 जॉन ग्लेन, 76 फिर से अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं। यूएसए के नासा ने यह घोषणा की है।

2009 हडसन नदी में डूबने से सभी 155 यात्री अमेरिकी वायुमार्ग के विमान में बच गए।

2009 यूएस एयरवेज़ फ्लाइट 1549 के बाद न्यू यॉर्क शहर से अपनी शुरुआती चढ़ाई के दौरान कनाडा के एक झुंड के झुंड को मारा, कैप्टेन चेसले सुलेनबर्गर ने हडसन नदी में आपातकालीन लैंडिंग की।

2010 उत्तरी अल्जीरिया में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा सेना के कर्नल और बेजायजा के एक सैन्य कमांडर को मार दिया गया।

2011 ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ के कारण ग्रामीण विक्टोरिया में 13,000 डोलर की संपत्तियां नष्ट हो गईं।

2012 जॉन हंट्समैन, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक उम्मीदवार मिट रोमनी का समर्थन करते हुए दौड़ से बाहर हो गए।

2013 सीरिया की अलेप्पो यूनिवर्सिटी में रॉकेट हमले में 83 लोगों की मौत हुई और 150 लोग घायल हुए।

2014 विश्व बैंक के वैश्विक जंगल की एक भविष्यवाणी है कि 2013 में 2.4 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अंतरिक्ष की भावी भूमिकाओं की नींव तैयार

अभिषेक कुमार सिंह

भरोसेमंद रॉकेट बनाकर सस्ती लागत के साथ उपग्रहों का प्रक्षेपण करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दुनिया में जो प्रतिष्ठा हासिल की है, उसने इसे एक विश्वसनीय और सुदृढ़ भविष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने वाले संगठन के रूप में स्थापित कर दिया है। इस संगठन के इन्हीं इरादों की एक नजीर हाल में तब मिली, जब 2024 खत्म होते-होते 30 दिसंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट पीएसएलवी-सी60 की मदद से अपना एक नया मिशन-स्पेडेक्स सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। स्पेडेक्स मिशन का महत्व इससे समझा जा सकता है कि स्पेस स्टेशन, गगनयान और चंद्रयान-4 समेत अब जो मिशन इसरो संचालित कर रहा है, उनमें स्पेडेक्स मिशन में होने वाले परीक्षणों की अहम भूमिका है।

खास तौर से अपने आखिरी चरण में जब तीन दिवसीय गगनयान मिशन से तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किमी ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा वाले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और जब स्पेस स्टेशन परिचालन में आएगा, तो उसमें स्पेडेक्स से डाली गई नींव अपनी भूमिका निभाएगी और उपयोगिता साबित करेगी। यह कैसे होगा, इसके लिए स्पेडेक्स अभियान की बारीकियों को समझना होगा, जो अपने परीक्षणों की सफलता के साथ भारत के भावी अंतरिक्ष अभियानों का ठोस आधार स्थापित करेंगी।

असल में, स्पेडेक्स मिशन में इसरो ने एसडीएक्स01 और एसडीएक्स02 नाम के दो छोटे उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में 470 किमी ऊपर भेजे हैं। इनमें से पहला उपग्रह चेजर (पीछा करने वाले) यान की भूमिका में है, जबकि दूसरा वाला लक्ष्य या कहें कि टारगेट है। इनमें से प्रत्येक यान 220 किलोग्राम वजनी है और अपनी कक्षा में ये करीब 29 हजार किमी की गति से परिक्रमा कर रहे हैं। अगले दो साल की अवधि में ये उपग्रह अपनी कक्षा में रहते हुए तीन प्रमुख परीक्षणों को अंजाम देंगे।

इनमें पहला परीक्षण है डॉकिंग, दूसरा, डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों में ऊर्जा का हस्तांतरण करना और तीसरा उद्देश्य है अनडॉकिंग के बाद पेलोड का संचालन करना। कुल मिलाकर स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य स्पेस में दो अंतरिक्ष यानों को 'डॉक' और 'अनडॉक' करने के लिए आवश्यक तकनीक को विकसित करना है। एक अंतरिक्ष यान से दूसरे यान के जुड़ने या कनेक्ट होने की प्रक्रिया को 'डॉकिंग' और अंतरिक्ष में जुड़े दो अंतरिक्ष यानों को अलग करने की प्रक्रिया को 'अनडॉकिंग' कहते हैं। इस मिशन का दूसरा उद्देश्य डॉकिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दोनों अंतरिक्ष यानों में परस्पर ऊर्जा का हस्तांतरण करना भी है।

भविष्य में स्पेस रोबोटिक्स जैसे प्रयोगों में ऊर्जा हस्तांतरण की यह तकनीक काफी अहम साबित हो सकती है। समय-समय पर उपग्रहों की देखरेख (सैटेलाइट सर्विसिंग), लंबी दूरी के अंतरिक्ष अभियानों (इंटरप्लेनेटरी मिशनों) और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने में भी यह तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। अगले कई चरणों में परीक्षणों की सफलता तय करेगी कि यह मिशन कामयाब रहा या नहीं। हालांकि इसरो की

काबिलियत को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही भारत अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग-अनडॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा प्रमुख देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन यह क्षमता हासिल कर चुके हैं।

इनमें से सबसे पहले अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को अपने जेमिनी-8 मिशन के तहत उपग्रह जेमिनी को एक अन्य टारगेट अंतरिक्षयान एजेना के साथ डॉक किया था। इसके अगले ही साल 30 अक्तूबर 1967 को सोवियत संघ (वर्तमान रूस) ने अपने दो उपग्रहों-कॉसमॉस 186 और कॉसमॉस 188 को स्वचालित तरीके से परस्पर डॉक किया था। उस समय अंतरिक्ष से यानों की वापसी के सिलसिले में अमेरिका और सोवियत संघ की इन उपलब्धियों के काफी बड़े मायने थे। चीन ने काफी बाद में 2 नवंबर 2011 को अपनी अंतरिक्ष-प्रयोगशाला तियांगोंग-1 के साथ बिना चालक दल वाले उपग्रह शेनझोऊ-8 को कामयाबी के साथ डॉक किया था।

अगर हम मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) की भूमिकाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि अंतरिक्ष में किसी यान या उपग्रह के लिए डॉकिंग या अनडॉकिंग प्रक्रिया का क्या महत्व है। असल में, आईएसएस का निर्माण ही कई टुकड़ों को जोड़कर या डॉकिंग के जरिये हुआ है। यही नहीं, इसकी अंदरूनी संरचनाओं में एक हिस्से से दूसरे हिस्से को डॉकिंग करके इस तरह जोड़ा गया है कि संपूर्णता में यह एक बड़े अंतरिक्षयान जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा जब यहां नए अंतरिक्ष यात्री रहने आते हैं और पहले से निवासित यात्री आए हुए स्पेसक्राफ्ट से वापस पृथ्वी की ओर रवाना होते हैं, तो वहां पहुंचे यान की डॉकिंग और अनडॉकिंग-दोनों प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं।

ऐसे में स्पष्ट है कि भारत जब डॉकिंग-अनडॉकिंग की यह क्षमता हासिल कर लेता है, तो स्वयं के स्पेस स्टेशन, गगनयान या चंद्रयान-4 आदि अभियानों में उसे इस तकनीक के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी कोई अन्य देश इस संबंध में सिर्फ मदद करता है, वह तकनीक का हस्तांतरण नहीं करता है। ऐसे में भारत द्वारा खुद इस तकनीक का विकास करना जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़ने और अलग करने की इस पूरी प्रक्रिया या डॉकिंग मैकेनिज्म पर भारत ने पेटेंट लिया है। पेटेंट मिल जाने पर डॉकिंग मैकेनिज्म को 'भारतीय डॉकिंग सिस्टम' नाम दिया गया है। इस तकनीक यानी 'इन-स्पेस डॉकिंग' की जरूरत उस समय और ज्यादा होती है, जब किसी एक ही साझा मिशन के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने पड़ते हैं और उनके अलग-अलग सामान अथवा उपकरण अंतरिक्ष में भेजे जाने होते हैं। इस नजरिये से देखने पर पता चलता है कि भारत जिस प्रकार से अगले कुछ ही वर्षों में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और गगनयान मिशन से अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने के इरादे से जो काम कर रहा है, वहां इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण व संचालन करने और चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्षयात्रियों को भेजने आदि योजनाओं के लिए इस तकनीक की काफी जरूरत होगी। अंतरिक्ष में चंद्रमा पर यात्रियों को यान से जिस मॉड्यूल में भेजकर चंद्र-सतह पर उतारा और वापस यान से मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा, वहां यह 'इन-स्पेस डॉकिंग' ही काम आएगी। डॉकिंग तकनीक 'चंद्रयान-4' जैसे दीर्घकालिक मिशनों और भविष्य में आयोजित किए जाने वाले दूसरे मिशनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

भारत के लिए खतरे की घंटी है चीनी परियोजना

प्रभाकर मणि तिवारी

चीन ने हाल में अरुणाचल से लगे सीमावर्ती इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा बांध बनाने का एलान किया है। इसने भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है। अब उस एलान को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल में सियांग बहुउद्देशीय परियोजना को शीघ्र हरी झंडी दिखाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोग विभिन्न वजहों से उस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। यारलुंग नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हुए असम पहुंचने पर उसका नाम बदल कर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। देश की सीमा पार बांग्लादेश पहुंचने पर यह नदी जमुना कहलाती है। चीनी बांध का बांग्लादेश में भी प्रतिकूल असर पड़ने का अंदेशा है। इस नदी की कुल लंबाई करीब 2880 किलोमीटर है। इसका 1625 किलोमीटर यानी आधे से ज्यादा हिस्सा तिब्बत में है। भारत और बांग्लादेश में इसकी कुल लंबाई क्रमश: 918 और 337 किमी है। चीन ने वैसे तो वर्ष 2021 में ही ऐसे बांध के निर्माण का संकेत दिया था। उस समय इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ही भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना का खाका तैयार किया था। लेकिन स्थानीय आदिवासियों के विरोध के कारण यह मामला फिलहाल आगे नहीं बढ़ सका है। चीनी परियोजना से 60 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी। चीन सरकार ने हालांकि दावा किया है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन भारत में पर्यावरणविदों का कहना है कि यह बांध अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के जिस इलाके में बनना है वह भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इस बांध से इलाके का पारिस्थितिकी संतुलन भी गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा निचले हिस्से यानी अरुणाचल प्रदेश और असम में इसकी वजह से खेती और जैव विविधता पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। पर्यावरणविदों की चिंता की वजह यह है कि पहले भी इलाके में ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं हो चुकी हैं। वर्ष 2000 में यारलुंग सांगपो की सहायक नदी ईगोंग सांगपो में भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश व असम में आई भयावह बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान हुआ था। इसी तरह वर्ष 2017 में आए भूकंप से इलाके में दो अस्थायी झीलें बन गई थी। भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि वह दोनों झीलें हल्के भूकंप की स्थिति में भी फट कर इलाके में तबाही मचा सकती हैं। चीन के एलान के बाद इसके मुकाबले के लिए इलाके में सियांग बहुउद्देशीय परियोजना को शीघ्र लागू करने की मांग बढ़ रही है। लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इस परियोजना के कारण इलाके के 13 गांव पूरी तरह डूब जाएंगे और 34 गांवों के लोगों की आजीविका और जीवन प्रभावित होगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री चाउना मीन कहते हैं कि स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचा कर कोई बांध नहीं बनेगा। लेकिन यह परियोजना चीनी परियोजना के खतरों से निपटने के लिए बेहद अहम है। उनका कहना है कि आम लोगों की राय और सार्वजनिक सुनवाई के बाद ही यह परियोजना आगे बढ़ेगी। मीन कहते हैं कि यह परियोजना महज पनबिजली के लिए नहीं बल्कि चीनी खतरों से निपटने के लिए बी जरूरी है। अगर चीन ने अतिरिक्त पानी छोड़ दिया तो ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर गुवाहाटी के सरायघाट ब्रिज तक सब कुछ डूब जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी चीनी परियोजना पर चिंता जताते हुए कहा है कि चीनी परियोजना पूरा होने की स्थिति में ब्रह्मपुत्र का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह नाजुक हो जाएगा। पूरा इलाक सूखे की चपेट में आ जाएगा और हमें खेती के लए भूटान और अरुणाचल प्रदेश में होने वाली बारिश पर निर्भर रहना होगा। इसी तरह चीन के पानी छोड़ने पर पूरा इलाका डूब जाएगा।

अनेकता में एकता का प्रतीक महाकुंभ

निरंकार सिंह

इस साल दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय समागम का महाकुंभ पर्वोत्सव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी के संगम पर 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। अनेकता में एकता का जीता-जागता प्रतीक पर्व है कुंभ मेला। लोक-पर्व होकर यह मेला सहस्त्र वर्षों से जन-विश्वास का आधार बना रहा है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा यह महाकुंभ पर्व, भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक अवधारणाओं का जीवन प्रतीक है। कुंभ पर्व, देश के समवेत सांस्कृतिक जीवन का व्यावहारिक उदाहरण है। इन्हीं पर्वों-मेलों ने हमारी भारतीयता (राष्ट्रीयता) को प्राणवान बनाए रखा है।

हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ पर्व की इस सांस्कृतिक विरासत को हमारे देश के मनीषी चिन्तकों, पुराणकारों ऋषि-मुनियों, दार्शनिकों, धर्माधिकारियों अथवा साधु-सन्तों ने लोकांचलों में निवास करने वाले पठित-अपठित साधारण जनों तक पहुंचाया है। इस पर्व भावना के पीछे जीवंत आस्था और निष्ठा भाव ही कार्यशील रहा है। भारत भूमि का यह खंड यदि पवित्र और महत्वपूर्ण है तो इसलिए कि वह बाकी विश्व से जोड़ता है, इसलिए नहीं कि वह उसे दूसरों से अलग करके भूगोल की राष्ट्रीय सीमाओं में बांध देता है। विश्वासों की इन मर्यादाओं के परिवेश में ही एक मानव समूह की जीवन धारा, उसकी लय और लौ रूपायित होती है। यह उसकी सांस्कृतिक चेतना का मुख्य प्रेरणा स्रोत भी है। यह भावना भारत को या भारतीय सभ्यता को आधुनिक दुनिया के राष्ट्रों और राज्य-तंत्रों से अलग कर देती है। इसलिए हमारी संस्कृति सभ्यता को गुलामी के कालखंड से नष्ट करने की तमाम कोशिशों के बावजूद हम ज्यूं के त्यूं खड़े हुए हैं। कुंभ या महाकुंभ जैसे पर्वोत्सव मेलों से भी हमें यह शक्ति प्राप्त

होती रही है। इस प्रकार शरीर रूपी घट में निहित अमृत तत्व की अनुभूति का विषय हो तो कुंभ-पर्व के रूप में अमृत पद प्राप्ति के लिए युग-युगों से भारतीय जन जीवन को आस्थाशील बनाए हुए है। कुंभ रूप इस लोक पर्व में भी 'मृत्यर्मामृतं गमय' की कामना, मरणशील मानव के मन को उद्वेलित एवं प्रेरित करती रही है। वही प्रेरणा, अनादि स्रोत सलिला सरिताओं के तट की ओर, भारतीय मन को सदा से आर्ज़षित करती रही है। निष्कर्ष रूप में कहें तो कह सकते हैं कि इन कुंभ पर्वों ने भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक एकता बनाए रखकर राष्ट्रीय जीवन संदर्भों के प्रति जातीय अस्मिता को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई है। जब कोई महाकुंभ पड़ता है तब जन भावना, उमंगित हृदय और संकल्पित मस्तिष्क को लेकर कुंभ स्थलों की ओर उमड़ पड़ती है। हर आयु वर्ग एवं जाति-वर्ग के लोग, प्रदेशों की सीमाओं को लांघते हुए गरीब-अमीर के दायरों को तोड़ते हुए अनेक भाषा-बोलियों में शब्द-साधना करते हुए परम अमृत की कामना से अपने 'स्व' (सीमित) को 'पर' (परम) में समर्पित करने के लिए संकल्पशील दिखाई देते हैं।

सागर-सरिताओं के तट पर ऐसे आस्थाशील श्रद्धालुओं के गतिशील चरण, भारत भूमि के कण-कण को, रागात्मक संबंधों से जोड़ते हुए महाराग का वस्त्र बुनते रहे हैं। सरिताओं के तट पर विशाल जन समाज को देखकर ऐसा लगता है मानो नए भाव-विधान वाले ऐसे आस्थाशील लोगों का एक नया नगर ही बस गया हो। यह जन-आस्था निर्जन प्रदेश को भी जनाकूल बना देती है। सालों साल प्रयाग के त्रिवेणी के तट पर कुंभ या अर्द्धकुंभ के बाद इस बार महाकुंभ का पावन अवसर आया है। जहां सैंकड़ों झोंपडियां, लाखों ध्वजा पताकाएं दिखाई देती हैं। यहां नाना वेशधारी साधु-सन्तों के संगठनों की अथवा नाना योगियों की जमातें अपनी परम्पराओं को निभाने के लिए अपनी आन-बान-शान के साथ अपना नाम अस्तित्व प्रदर्शित कर रही हैं। पवित्र कुंभ का रंग ही ऐसा होता है, जो हर तरह के पर्यटकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करता है। जो लोग भारत दर्शन के लिए आना चाहते हैं, उन्हें पूरे भारत की विविधता एक जगह सिमटी हुई मिल जाती है और जो लोग आध्यात्मिक टूरिज्म पर आना चाहते हैं, उनके लिए तो इससे भव्य आयोजन कोई हो ही नहीं सकता।

चीनी यात्री ह्यू एन सांग (सन् 629-45ई.) ने अपने यात्रा विवरणों में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग के कुंभ-अर्द्धकुंभ पर्वों पर सर्वस्व दान करने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार हरिद्वार में सम्पन्न होने वाले कुंभोत्सवों का भी अपना विशेष महत्व रहा है। अकबर बादशाह ने ऐसे ही अवसरों पर तीर्थ यात्रियों पर लगने वाला जजिया सन् 1564 ई. में उठा लिया था किन्तु औरंगजेब ने हरिद्वार में पडने वाले कुंभ से पहले ही सन् 1678-79 में जजिया फिर से लगा दिया था। इस बार के महाकुंभ को योगी आदित्यनाथ ने दिव्य भव्यता के साथ डिजिटल भी बना दिया है। आज सामाजिक-सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन के माहौल में जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय एकता के खतरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों के समायोजन की बड़ी आवश्यकता अनुभव की जाती है।

टूडो के उत्तराधिकारी को चुनौतियों से निपटना होगा

कल्याणी शंकर

इस सप्ताह, महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाली 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं वैश्विक स्तर पर ध्यान देने योग्य हैं। पहली घोषणा वेटिकन की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है,जिसने सिस्टर सिमोना ब्रैम्बिला को 'प्रीफैक्ट' के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें सभी कैथोलिक चर्च के धार्मिक आदेशों की देख-रेख का काम सौंपा गया है। इससे पहले किसी महिला ने यह पद नहीं संभाला था। यह नियुक्ति पोप फ्रांसिस के चर्च को संचालित करने में महिलाओं को अधिक नेतृत्वकारी भूमिकाएं देने के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2022 से पहले,'वेटिकन डिकास्टरी' का नेतृत्व करने वाली एक महिला की कल्पना करना कठिन था। यह तब बदल गया जब पोप फ्रांसिस ने 'प्रिडिकेट इवैंजेलियम'पेश किया। इस दस्तावेज ने रोमन क्यूरिया के शासन में सुधार किया। इसने सभी कार्यालयों को 'डिकास्टरीज' के रूप में जाना और उन लोगों को अनुमति दी जो पुजारी या बिशप के रूप में नियुक्त नहीं हैं।

59 वर्षीय सिस्टर ब्रैम्बिला एक कंसोलटा मिशनरी हैं, जो एक धार्मिक आदेश सदस्य हैं और पिछले साल से आदेश के विभाग में दूसरे स्थान पर हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पद को लंबे समय से एक महिला द्वारा धारण किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता रहा है। कुछ समय पहले, वैश्विक कैथोलिक नेताओं के एक महत्वपूर्ण वेटिकन शिखर सम्मेलन ने चर्च के भीतर महिलाओं को अधिक महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिकाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में 100 देशों के कार्डिनल, बिशप और नागरिक शामिल हुए। इसमें चर्च के भीतर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। महिला उपयाजकों से संबंधित प्रस्ताव के पक्ष में 258 वोट और विपक्ष में 97 वोट मिले। पोप फ्रांसिस ने पहली बार महिलाओं को वोट देने का

अधिकार भी दिया। यह कैथोलिक चर्च के मामलों में महिलाओं को अधिक असाधारण निर्णय लेने की शक्ति देने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। उच्चतम स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चर्च के भीतर लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। उन्होंने महिलाओं को उपयाजकों के रूप में नियुक्त करने पर विचार करने के लिए 2 वेटिकन आयोग बनाए थे।

दूसरी घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बनने की दौड़ भी जुड़ी हुई थी। वर्तमान परिवहन मंत्री अनीता आनंद इस दौड़ में एक प्रमुख उम्मीदवार थीं। मगर उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया है। आनंद कनाडा की लिबरल पार्टी की वरिष्ठ सदस्य हैं। ट्रूडो एक दशक से सत्ता में हैं, जिसमें सफलताएं और चुनौतियां दोनों हैं। उन्होंने इस साल के चुनाव में चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लडने की योजना बनाई थी। लेकिन देश-विदेश में बढ़ती चुनौतियों के बीच उन्हें पद छोडना पड़ा। ट्रूडो के इस्तीफे से उनके राजनीतिक करियर और कठिनाइयों का समापन हुआ, जो बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुआ था।

उन्हें मुद्रास्फीति, आवास संबंधी मुद्दों और आव्रजन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे लिबरल पार्टी कमजोर हो गई। अगर अनीता आनंद निर्वाचित हो जातीं तो वह कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रचतीं, जो अश्वेत और भारतीय मूल की हैं। उनका चुनाव कनाडा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता था, खासकर राजनीति में महिला सशक्तिकरण के मामले में। ट्रूडो के उत्तराधिकारी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, नवाचार मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन संभावित दावेदारों में से हैं। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। हाल के महीनों में कनाडा और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। यह तनाव तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जून 2023 में सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी की गोलीबारी में हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। इस आरोप ने दोनों देशों के बीच संबंधों को काफी हद तक तनावपूर्ण बना दिया है।

इस बीच, नई दिल्ली ने कनाडा के नए वीजा को निलंबित कर दिया। इसने कनाडा से भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम करने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा ओटावा से अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को भी वापस बुला लिया। कई अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुलाया गया। लिबरल नेतृत्व के लिए अन्य अग्रणी उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी और पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं, जिनके पिछले महीने अचानक इस्तीफे के कारण ट्रूडो को बाहर होना पड़ा। उम्मीदवारों को 23 जनवरी तक चुनाव लडने का इरादा घोषित करना होगा और 350,000 कनाडाई डॉलर का प्रवेश शुल्क देना होगा। ट्रूडो के उत्तराधिकारी को पार्टी की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए इन विवादों और नीतिगत चुनौतियों से निपटना होगा। मुख्य चुनौती पार्टी की छवि को सुधारना है, जो ट्रूडो के नेतृत्व के पिछले 10 वर्षों में कम हुई है। उत्तराधिकारी को भारत और अमरीका के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना होगा और आव्रजन बैकलॉग का प्रबंधन करना होगा।

खाद्य नीति में डॉ. मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता

टी नंद कुमार

जून 2006 का अंतिम सप्ताह था। मैं झारखंड में तीन काम संभाल रहा था-विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष विद्युत बोर्ड। अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट से लौटने के बाद मैं अक्तूबर तक भारत सरकार में पोस्टिंग की उम्मीद कर रहा था। एक दोपहर मुझे कैबिनेट सचिव के कार्यालय से फोन आया कि मुझे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में 'विशेष सचिव' नियुक्त किया गया है और मुझे तुरंत दिल्ली में रिपोर्ट करना है। मैं अचानक हुए बदलाव के लिए तैयार नहीं था। उस विभाग के लिए मेरा चयन, जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं था, मेरे लिए एक आश्चर्य था। मैंने आदेश का पालन किया और दिल्ली आ गया।

विभाग पूरी तरह तैयार था। कई वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार भारत को पर्याप्त मात्रा में गेहूं का आयात करना था। प्रक्रिया शुरू तो कर दी गयी थी, पर वह अपेक्षित गति नहीं पकड़ पायी थी। सरकार के भीतर प्रक्रियाओं और नौकरशाही स्तर पर विलंब ने चीजों को धीमा कर दिया था। मैंने अगले दिन प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुझे 'राष्ट्र' के लिए काम करने के लिए कहा। यह मेरे लिए शीर्ष स्तर से मिला प्रोत्साहन था। मैं काम में लग गया और प्रक्रिया तेज कर दी। नतीजे दिखने लगे। ऐसी कई बैठकें हुईं जिनमें प्रधानमंत्री ने स्वयं खाद्य पदार्थों की स्थिति पर चर्चा की। एक दिन पीएम से 'वन टू वन' मीटिंग के दौरान, मैंने उनसे विशेषज्ञ द्वारा की जा रही आलोचना के बारे में पूछा, जिसमें कहा जा रहा था कि ऊंची कीमतों पर गेहूं का आयात करना गलत है और यह आगे जाकर हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा।

उन्होंने कहा, मैं किसी भी भारतीय को भोजन के बिना नहीं रहने दे सकता। कमी है और आपूर्ति बढ़ानी होगी। हमें मांग कम

करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा है और अगर हम अपने लोगों के लिए भोजन नहीं खरीद सकते तो इस भंडार का क्या अर्थ है। बाद में हुई एक बातचीत में मैंने प्रश्न उठाया कि हम एक या दो वर्ष से ज्यादा आयात पर निर्भर नहीं रह सकते, हम भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे बचें? उन्होंने इस प्रश्न पर कई अन्य प्रमुख मंत्रियों और विशेषज्ञों से सलाह ली। इसके बाद उन्होंने दो योजना बनायी- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से यह भिन्न था) को लॉन्च करने की, ताकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ायी जा सके।

आरकेवीवाइ की परिकल्पना राज्य के नेतृत्व वाले केंद्र समर्थित कार्यक्रम के रूप में की गयी थी, जहां संपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य के मुख्य सचिवों को सौंपी गयी थी। एनएफएसएम का लक्ष्य मुख्य रूप से बाजरा और दालों के एक छोटे घटक के साथ गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाना था। इसे कृषि मंत्रालय ने लागू किया और भारत ने अपने उत्पादन को ऐसे स्तर तक बढ़ाया गया, जो आरामदायक स्थिति से भी अधिक था। इसके लिए 4500 करोड़ रुपये की राशि (5000 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले) खर्च की गयी। कार्यक्रम के अंत (2012) में समीक्षा में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 2006-07 के आधार वर्ष के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में चावल उत्पादन में 12.1 मिलियन टन (लक्ष्य 10 मिलियन), गेहूं में 19.1 मिलियन टन (लक्ष्य आठ मिलियन) और दाल उत्पादन में 2.9 मिलियन टन (लक्ष्य दो मिलियन) की वृद्धि हुई है। यह सर्वोत्तम योजना और उसका कार्यान्वयन था। एक अन्य अवसर पर मुझे उनके साथ एफसीआइ में बफर स्टॉक की मात्रा पर चर्चा करने का अवसर मिला। जहां मेरे सुझाव को तुरंत मान लिया गया।

वर्ष 2008 वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की गंभीर कमी और कई देशों में इस कारण हुए दंगों के लिए जाना जाता है। दुनिया में अनाज की कमी होने से बहुत पहले, हमने देश के 'अनाज बजट' पर विचार करने की कवायद शुरू कर दी थी। इसमें एफसीआइ स्टॉक के अतिरिक्त निजी तौर पर रखे गये स्टॉक का अनुमान भी शामिल था। तब अधिकांश खाद्य नीति निर्णय सार्वजनिक स्टॉक (एफसीआइ+राज्य) के आसपास केंद्रित थे और ऐसा लगा था कि यह 2006 जैसी स्थिति से बचने के लिए अपर्याप्त थे। हमने पाया कि चावल की स्थिति चिंताजनक है। जब मैंने ये आंकड़े और अपनी आशंका पीएम के सामने रखी, तो उन्होंने मूल्य को लेकर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलायी। मंत्रालय ने कहा कि गैर-बासमती चावल निर्यात पर अस्थायी रोक लगायी जा सकती है। अन्य लोगों के साथ, निर्यातकों और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियों ने इसका कड़ा विरोध किया, पर डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे देशों में चावल भेजने से पहले मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में हमारे लोगों के लिए पर्याप्त चावल हो। उनके इस कदम की भी आलोचना हुई। पर डॉ सिंह स्पष्ट थे कि वे क्या चाहते हैं। इसी दूरदर्शिता के कारण 2009 के भीषण सूखे को खाद्यान्नों के आयात के बिना प्रबंधित किया जा सका। व्यक्तिगत स्तर पर, मैं डॉ सिंह का एक छात्र था और वह मेरे पथ-प्रदर्शक, मार्गदर्शक और गुरु थे।

ठंड के मौसम में डैंड्रफ से हैं परेशान तो इन आसान उपाय को अपनाकर पाएं छुटकारा

ठंड के मौसम में डैंड्रफ होने की समस्या आम हो जाती है। ये सिर्फ हमारे बालों को नुकसान ही नहीं पहुंचाती बल्कि शर्मिंदा भी करती है। इसे दूर करने के लिए कैमिकल युक्त शैम्पू, कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय कुछ अन्य उपाय किए जाएं, तो बालों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है आइए जानते हैं कुछ टिप्स.

नारियल का तेल

नारियल का तेल रूसी के लिए एक बेहतरीन उपाय है। नहाने से पहले 4-5 चम्मच नारियल के तेल से मालिश करें और 1-2 घंटे बाद बालों को धो लें। रातभर लगाकर भी छोड़ सकते हैं। इससे डैंड्रफ में राहत मिलती है। ऐसा शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते है जिसमें नारियल तेल हो।

शैम्पू करने से पहले डैड्रफ को साफ करने के लिए नमक बहुत कारगर है। नमक को स्कैल्प पर डालकर हल्कें हाथों से रगड़ें इससे मृत त्वचा निकलने लगेगी। कुछ देर रगड़ने के बाद शैम्पू कर लें। आप पाएंगे कि डैंड्रफ पहले से काफी कम हो रहे है। जब भी शैम्पू करें इस प्रक्रिया को अपनाएं कुछ ही समय में डैंड्रफ से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा।

नींबू का रस

दो चम्मच नींबू के रस को अपने बालों के स्कैल्प पर रगड़कर इससे अच्छी तरह से मालिश करें। फिर एक कप पानी में एक नींबू का रस मिलाएं अब इस पानी से अपने बालों को साफ करें। ऐसा आप हफ्ते में 3 बार करें।

नारियल और नींबू का रस

नारियल के तेल में एक चम्मच नींबू का रस डालकर इन्हें हल्का गर्म कर लें। अब इस तेल से अपने बालों की मसाज करें। फिर शैम्पू से अपने बालों को धो लें। ये प्रक्रिया आप हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करें।

कामकाजी महिलाओं को हमेशा रखना चाहिए इन बातों का ध्यान

शादी के बाद एक लड़की को अपने पति से ही नहीं बल्कि अपनी सास-ससुर से भी अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। लेकिन तब क्या हो जब आप घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही हों।

वो जमाना गया जब महिलाएं घर की चार दीवारी में रहकर ही अपना पूरा जीवन काट देती थीं। आज की महिलाएं न केवल अपने अधिकारों को लेकर स्वतंत्र हैं बल्कि पुरुषों की तरह घर से बाहर निकल अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाब हो रही हैं। हां, वो बात अलग है कि लाख-पढ़ी लिखी होने के बाद भी लड़कियों को ससुराल जैसी पारंपरिक भूमिकाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें न केवल अपने पति के दिल में जगह बनानी होती है बल्कि अपने सास-ससुर संग एक अच्छे रिश्ते की शुरूआत करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी में से एक है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कामकाजी महिलाओं के साथ है, जिन्हें हर पल इस बात की चिंता सताती रहती है कि घर और ऑफिस के बीच क्या वह अपनी संतुलन भूमिकाएं निभा भी पाएंगी या नहीं?

खैर, हम इस तर्क-वितर्क से किसी नतीजे पर पहुंचें उससे पहले आपको बता दें कि जहां कुछ महिलाओं ने एक संयुक्त परिवार में रहने के कई दोष बताएं हैं तो वहीं इसके विपरीत कई कामकाजी महिलाओं का ऐसा कहना है कि एक संयुक्त परिवार में रहना आपके लिए एक मजबूत समर्थन बन सकता है बशर्ते आपको काम और घर के बीच बैलेंस बनाना आता हो। ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि कम समय में ही आप सभी की लाडली बन जाए तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखें।

काम के साथ घर को भी प्राथमिकता

हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि एक लड़की के लिए उसका करियर कितना महत्व रखता है लेकिन शादी के बाद आपको यह भी समझना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं है आपका अपना एक परिवार है, जिसके हिसाब से भी अब आपको चीजों को मैनेज करना होगा। शादी से पहले जहां घंटों-घंटों आप ऑफिस में काम करती थीं तो वहीं अब आपको अपने परिवार के लिए भी समय निकालना होगा साथ ही साथ घर खर्च के हिसाब से लेकर पार्टनर के माता-पिता की देखरेख करने तक आपको कई बातों को भी ध्यान रखना होगा।

सुनें और समझें

अगर आप वाकई में चाहती हैं कि आप काम के साथ-साथ अपने परिवार की भी लाडली बनी रहीं तो सबसे पहले बातों को सुनने और समझने की आदत डालें। ऐसा करने से न केवल आप अपने सास-ससुर के मन की बातों को जान पाएंगी बल्कि वह भी आपके काम के महत्व को समझेंगे। यही नहीं, अपने परिवार के हर सदस्यों को जानने की कोशिश करें। यही नहीं, साथ ही साथ उन्हें यह भी बताएं कि घर की जिम्मेदारी को निभाने में आपके लिया क्या संभव है और क्या नहीं।

पति से हो खुलकर बातचीत

किसी ने ठीक ही कहा है कि सबसे अच्छी शादी वह होती है जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हों। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्यार करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसे में कोशिश करें कि आप और आपके पति के बीच एक स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता हो। इसके बाद आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुद फर्क समझ आ जाएगा। वह न केवल आपको समझेंगे बल्कि आपको घर-परिवार की जिम्मेदारी का एहसास होगा।

पहली मुलाकात में जानें एक-दूसरे को

जब भी कपल्स एक-दूसरे से मिलने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले जेहन में ये बात जरूर आती है कि आखिर पहली मुलाकात में हम बात क्या करेंगे? यही सवाल हमें परेशान करता रहता है और वैसे भी पहली-पहली मुलाकात तो बहुत खास होती है, जो हमेशा याद रहती है।

लेकिन इस मुलाकात में हम एक-दूसरे से बात ही न कर पाएं या यूं कहें कि उस समय क्या बात करें? ये समझ ही न आए तो क्या करें? क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि हमारे मन में बातें तो ढेरों रहती हैं, लेकिन पहली मुलाकात पर वे बातें जुबान पर आ ही नहीं पातीं और हम शांत बैठे रह जाते हैं। और यहां-वहां देखकर बस यही सोचते रह जाते हैं कि बातें करें तो क्या? आखिर क्या बातें फर्स्ट मीटिंग में करें? कैसे बातों से एक-दूसरे को समझने में आसानी हो सकती है? ऐसी कौन सी बातें हैं, जो आपके पार्टनर को बोर नहीं होने देंगी? आइए जानते हैं।

जब भी किसी के साथ पहली मुलाकात के लिए जाएं तो बातों की शुरुआत आप उनके प्रोफेशन से कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसमें इंट्रेस्ट जरूर आता है। चाहे प्रोफेशन के बारे में गॉसिप अच्छी हो या बुरी, इस बारे में बात करना लोग काफी पसंद करते हैं। पार्टनर के फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में आप पूछ सकते हैं या अभी रिसेंट उन्होंने कौन सी मूवी देखी है? इस बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तारीफ किसको पसंद नहीं आती? जनाब तो कॉम्प्लीमेंट करना बिलकुल भी न भूलें। उन्हें नोटिस करें और उनकी तारीफ कीजिए। आप उनके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर सकते हैं। दोस्तों के बारे में बात करें, क्योंकि लड़का हो या लड़की-सभी को अपने दोस्तों के बारे में बात करना पसंद आता है। तो आप पूछ सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? किस फ्रेंड्स से अपनी बातें शेयर करते हैं? इस तरह की बातें आपकी मुलाकात को और इंट्रेस्टिंग बनाएंगी। वीकेंड के बारे में पूछें कि उनके इस वीकेंड क्या प्लान हैं? यदि कोई प्लान नहीं हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं जिससे कि एक-दूसरे को अच्छे से समझने के लिए और समय मिल सके। अगर बातें बोरिंग हो रही हैं तो आप हंसी-मजाक कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा वाकया कब हुआ, जब उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। ऐसी कोई फनी बात, जो आपके साथ हुई हो तो वह बात भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं।

कुर्ते से लगें स्मार्ट

कुर्ते आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, जितने पहले थे। बस, इसकी स्टाइल में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। आजकल पाकिस्तानी सूट ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। लड़कियां जोधपुरी शैली के सलवार कुर्ते भी बनवाना पसंद करती हैं। ये कुर्ते ढीले-ढाले और कई रंगों में उपलब्ध होते हैं। आम तौर पर लोगों की राय है कि आज के आधुनिक युग में लड़कियां जींस आदि पहनना ही पसंद करतीं हैं और सलवार कुर्ते तथा अन्य पारंपरिक कपड़ों का चलन कम हो रहा है, लेकिन फैशन डिजाइनरों की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि आज भी लड़कियां सलवार कमीज बनवाना पसंद करतीं हैं और अब तो इसमें रेट्रो फैशन की झलक भी देखने को मिल रही है। आजकल तो लड़कियां जींस के साथ भी लांग और शार्ट कुर्ते पसंद करतीं हैं। सलवार के साथ शार्ट कुर्ते या अनारकली स्टाइल के कुर्ते ज्यादा देखे जा रहे हैं। संगीता का कहना है कि कुर्ते को जींस, लेगिंस और जेगिंस, मतलब डेनिम स्टाइल की जींस की तरह दिखने वाली सलवार के साथ पहनने का फैशन काफी प्रचलन में है। केवल सलवार कमीज ही नहीं, दुल्हन के लहंगों में भी आधुनिकता और पारंपरिकता का मिश्रण देखने को मिल रहा है। सलवार कमीज का जादू कुछ और ही होता है। इस आउटफिट में थोड़ी सी तब्दीली करते ही इसे इंडो वेस्टर्न लुक दिया जा सकता है। आइए जानते हैं सलवार-कुर्ते से जुड़े कुछ टिप्स-

अगर आप अपनी हाइट थोड़ी ज्यादा दिखाना चाहती हैं, तो थोड़ा लंबा कुर्ता सिलवाएं। मसलन अगर आपकी हाइट 5'3'' है तो आपको 47-48 इंच का कुर्ता सिलवाना चाहिए।

अगर आपके हाथ मोटे हैं और आप स्लीवलेस नहीं पहन सकती हैं, तो 5 इंच की स्लीव्स बनवा लें। इससे आपके हाथ का अतिरिक्त मांस भी छिप जाएगा और आपके हाथ दुबले दिखेंगे। सलवार को बहुत सारे स्टाइल्स में पहना जा सकता है। इनका स्टाइल भी ट्रेंड के साथ बदलता रहता है। फिलहाल ढीली सलवार फैशन में है और शॉर्ट कुर्ते ने एक बार फिर एंट्री की है।

क्या आप जानते हैं लेगिंग्स पहनने का सही तरीका

जब भी कम्फर्ट की बात आती है तो सबसे पहले हम लेगिंग्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि लेगिंग्स काफी आरामदायक होती है। लेकिन इसे पहनने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं।

क्या आप जानती हैं लेगिंग्स पहनने का सही तरीका? अगर हां तो यह बहुत बढ़िया बात है और यदि आपका जवाब ना है तो इस लेख को पढ़कर आप इस बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं।

हमने अक्सर ऐसी कुछ महिलाओं को देखा है, जो लेगिंग्स के साथ क्रॉप टॉप ट्राई कर लेती हैं। लेकिन यदि आप भी ऐसी गलती करती हैं तो इसे छोड़ दें, क्योंकि लेगिंग्स के साथ कभी भी क्रॉप टॉप नहीं पहना जाता। यह दिखने में बहुत भद्दा लगता है।

ये तो बात हुई क्रॉप टॉप कि लेकिन अगर आप छोटे टॉप पर लेगिंग्स पहनने का विचार कर रही हैं तो इसे बिलकुल भी ट्राई न करें, भले ही आप कितनी भी स्लीम ट्रीम क्यों न हों, पर छोटे टॉप के साथ लेगिंग्स की यह स्टाइल आप पर बिलकुल अच्छा नहीं लगेगी। आपको ऐसी अंडरवियर पहनना चाहिए जिसमें हेमलाइन लेगिंग्स के ऊपर नजर न आए। ऐसे लेगिंग्स पहनने में बहुत अजीब सा लगता और आप इसमें कम्फर्टेबल भी नहीं रह सकती हैं।

प्रिंटेड लेगिंग्स को न करें ट्राई

आप प्रिंटेड लेगिंग्स ट्राई न ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये पहनने में बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए अगर आप लेगिंग्स लेने जा रही हैं, तो प्रिंटेड लेगिंग्स न ही लें तो बेहतर है।

पाएं हाई हील्स की तकलीफ से छुटकारा

अधिकतर लड़कियां हिल्स पहनना तो चाहती है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसे पहनना काफी तकलीफभरा हो सकता है, लेकिन एक अच्छी और स्टाइलिश ड्रेस के साथ हिल्स काफी अच्छी लगती है पर पैरों की तकलीफ के कारण इसे नहीं चुनते हैं। लेकिन हम यहां आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे है जिन्हें अपनाकर आप हाई हिल्स में कंफर्टेबल हो सकती है हम ये नहीं कहते कि हिल्स में आप बहुत आरामदायक महसूस करेंगी लेकिन कुछ टिप्स को अपनाकर आप हाई हिल्स पहनने से होने वाली दिक्कतों से बच सकती हैं.तो आइए, जानते हैं कि हाई हील्स पहनने के दौरान होने वाली परेशानी को आप कैसे कम कर सकती हैं

सैंडिल के सही साइज का चुनाव करें

हील्स वाली सैंडिल में आपके पैर आगे की ओर पुश होते हैं, ऐसे में अपने लिए सही साइज की सैंडिल का चुनाव करें।

अपना फुट टाइप पहचानें

सभी के फुट अलग-अलग होते हैं, किसी के पैर के पंजे चौड़े तो किसी के पतले होते हैं। अपने पंजे के अनुसार सैंडिल के आगे की डिजाइन चुनें, जिससे कि आपके पैर आगे से दबे नहीं।

मोटी हील को प्राथमिकता दें

मोटी हील आपके पैरों को ज्यादा कवरेज और सपोर्ट देती हैं। इसे पहनने से आपकी एड़ियों पर कम दबाव पड़ेगा, जिससे पैरों में दर्द भी कम होगा।

ब्रेक लें

पार्टी व किसी खास अवसर पर ही हाई हील्स पहनें। यदि इसके अलावा भी पहनें तो कभी-कभी फ्लेट चप्पल पहनें और अपने पैरों को थोड़ा ब्रेक दें।

हील की पोजीशन का ख्याल रखें

आपके जूते ऐसे होने चाहिए जिसमें बॉडी का भार पंजों और हील दोनों पर रहे। वरना पंजो या फिर हील पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसा होने पर पैरों में दर्द शुरू हो सकता है। इसलिए हील की पोजीशन का ख्याल जरूर रखें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को फसल कटाई के विभिन्न त्योहारों के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सभी की अच्छी सेहत के साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी कामना की। ज्ञात हो कि देश में आज मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ''सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य को समर्पित यह पावन उत्सव आप सबके जीवन में नयी ऊर्जा और उत्साह का संचार करे।'' मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम और तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। असम में इसे माघ बिहू और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। प्रधानमंत्री ने अलग-अलग भाषाओं में किए गए ट्वीट के जरिए देशवासियों को माघ बीहू और उत्तरायण की भी शुभकामनाएं दीं।

आतिशी ने कालकाजी सीट से दाखिल किया नामांकन पत्र

नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार आतिशी ने मंगलवार को लाजपत नगर में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कालकाजी सीट से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी ने चुनाव जीतने और 2013 से दबदबा बनाए रखने वाली आप की जगह लेने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र सोमवार को दाखिल नहीं कर सकीं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता ने दी। मुख्यमंत्री आतिशी ने गिरि नगर स्थित एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ एक रोडशो किया और फिर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर रवाना हुई।

पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही आप : केजरीवाल

नईदिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ मिनट बाद, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि भाजपा नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए खुलेआम नकदी बांट रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज होने पर केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चैन आदि बांटते हैं। फर्जी वोट बनवाते हैं। फिर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है। मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं।

मणिपुर का दौरा नहीं करने पर कांग्रेस का मोदी पर हमला

नई दिल्ली। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने एक बार फिर तीखा हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी ने मंगलवार को कहा कि पीएम के पास पूरी दुनिया घूमने के लिए समय और इच्छाशक्ति है, मगर पूर्वोत्तर राज्य में परेशान लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझ रहे। कांग्रेस ने यह टिप्पणी मणिपुर में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहली वर्षगांठ पर की। बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए पिछले साल 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। यह रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में समाप्त हुई थी। उन्होंने आगे कहा, मणिपुर को अभी भी प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार है, जिनके पास दुनिया भर में घूमने के लिए तो समय और इच्छाशक्ति है लेकिन वह मणिपुर के संकटग्रस्त लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं।

बीआरएस नेता केटी रामाराव और हरीश राव नजरबंद

हैदराबाद। बीआरएस नेता केटी रामाराव और टी हरीश राव को पुलिस ने मंगलवार को घर में नजरबंद कर दिया। बीआरएस विधायक पी कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हुजुराबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को जगतियाल सीट से कांग्रेस विधायक संजय कुमार के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। 12 जनवरी को करीमनगर में जिला समीक्षा समिति की बैठक में संजय कुमार को कौशिक रेड्डी ने कथित तौर पर अपशब्द कहे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। शिकायत के बाद कौशिक रेड्डी के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए और सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जगतियाल विधायक संजय कुमार के पीए द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार किया गया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री बोले-

अनुसंधान और नवाचार नए भारत के स्वभाव का एक हिस्सा : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के समारोह में भाग लिया और मिशन मौसम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के 150 वर्ष मना रहे हैं। ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा नहीं है, ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी यात्रा है। आईएमडी ने न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है।

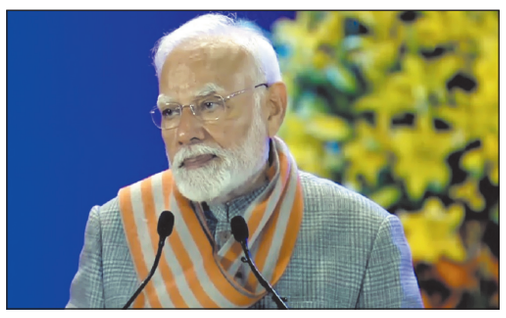

प्रधानमंत्री ने कहा, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति विज्ञान के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में अनुसंधान और नवाचार नए भारत के स्वभाव का एक हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी की आधारभूत संरचना और तकनीक का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम टिकाऊ भविष्य और भविष्य की तत्परता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा, मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्यकुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था।

उन्होंने कहा कि हमारी मौसम संबंधी प्रगति के साथ हमारी आपदा प्रबंधन क्षमता का निर्माण हुआ है। इसका फायदा पूरी दुनिया को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी मदद दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने मौसम विज्ञान की दक्षता को अधिकतम करने और प्रकृति को जिम्मेदार ठहराने वाली आपदाओं के प्रभाव को कम करने के महत्व को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार नए भारत के मिजाज का हिस्सा हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के मकसद से मिशन मौसम की शुरुआत की। राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक सिक्का और मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन-2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में आईएमडी की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

एनडीए के मुरीद हो गए संजय राउत

इंडिया ब्लॉक को लेकर दे डाली कांग्रेस को नसीहत

मुंबई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व में विश्वास व्यक्त किया और गठबंधन में बड़े भागीदार के रूप में कांग्रेस से विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए, राउत ने भाजपा के प्रभुत्व के सामने लोकतंत्र और विपक्षी एकता को बनाए रखने में इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जीवित रहेगा। अगर हम इंडिया गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। वे (बीजेपी) विपक्ष को खत्म कर देंगे।

राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था लेकिन आज इसे बरकरार रखना देश और लोकतंत्र की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आप को लगता है कि वे बड़ी ताकतें हैं। महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का है। वहां गठबंधन बनाना मुश्किल है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा (महाराष्ट्र) में हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा। गठबंधन में बड़ी पार्टी होने के नाते हमें एकजुट रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी है।

एनडीए वाले दिन याद करते हुए संजय राउत कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को त्याग करना चाहिए जैसा बीजेपी किया करती थी। उन्होंने कहा कि जब हम एनडीए में थे तो नेताओं और दलों के बीच लगतार बातचीत का दौर जारी रहता था। इससे पहले सोमवार को राउत ने कहा था कि आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन को बचाना है और मजबूत करना है तो गठबंधन सहयोगियों के बीच बातचीत जरूरी है।

राउत की टिप्पणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद आई है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इंडिया गुट विभाजित है। कई भाजपा नेताओं ने यह भी दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक के पास कोई मिशन नहीं है और वह बिखरा हुआ है। रविवार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया ब्लॉक की आलोचना करते हुए दावा किया कि गठबंधन पूरी तरह से विघटित हो गया है, उन्होंने गठबंधन द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव और मुंबई नगर निगम चुनाव एक साथ नहीं लड़ने का उदाहरण दिया।

उमर अब्दुल्ला ने पूरी लॉबी को दिखा दिया आईना

भाजपा बोली- कांग्रेस-आप-सपा को इससे सीखना चाहिए

नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा चुनाव कराने और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने के एक दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को शेष भारत से पूछा। अपने साथी से सबक सीखने के लिए ब्लॉक करें। यह दावा करते हुए कि उमर अब्दुल्ला ने भारत के चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने वाली लॉबी को आईना दिखाया है, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडिया ब्लॉक पर कटाक्ष किया और कहा कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और समाजवादी पार्टी को इससे सीखना चाहिए।

शहजाद पूनावाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी आप चुनाव जीतते हैं, तो आप चुनावी प्रक्रिया की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं, तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं... उमर अब्दुल्ला ने उन्हें आईना दिखाया है, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में गांदरबल जिले में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड-मोड़ सुरंग, जिसका नाम बदलकर सोनमर्ग सुरंग रखा गया है, का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी का स्वागत किया। वहां भीड़ को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने न केवल विधानसभा चुनाव कराने के वादे को पूरा करने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी मोदी की प्रशंसा की कि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी अनियमितता के स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सोमवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। ज़ेड-मोड़ सुरंग के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए, उमर ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद, श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया, जहां लोगों से वादा किया गया था कि चुनाव होंगे, और उन्हें मिलेगा।

शरद पवार ने भी दिए अकेले चुनाव लड़ने के संकेत

मुंबई। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। दरअसल हाल ही में शिवसेना यूबीटी ने स्थानीय चुनाव अकेले लड़ने का एलान किया था। अब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी भी स्थानीय चुनाव अकेले लड़ सकती है। दरअसल शरद पवार से जब इंडी गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में कभी भी राज्य और स्थानीय चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई। इंडी गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए था। महाराष्ट्र के आगामी निकाय चुनाव में हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले, इसका फैसला करने के लिए अगले 8-10 दिनों में बैठक होगी।

खेल
प्रमुख समाचार

इंग्लैंड, भारत को पछाड़ कर बना सकती है नया रिकॉर्ड

नईदिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज जल्दी ही शुरू होने वाली है। टीम इंडिया की घोषणा भी कर दी गई है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज के लिए मैदान पर उतरेगी। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम से यह एकदम अलग टीम है। टी20 क्रिकेट में फैन्स चौकों और छक्कों की बारिश देखना पसंद करते हैं। भारतीय टीम से कोलकाता के ईडन गार्डंस में होने वाले पहले टी20 में इसी तरह की उम्मीद होगी। हालांकि इंग्लैंड की मजबूत टीम भारत आ रही हैं, ऐसे में काम आसान नहीं कहा जा सकता है।

भारतीय टीम ने इंग्लैंड को टी20 में डोमिनेट किया है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। इंग्लिश टीम सबसे छोटे प्रारूप में भारत के सामने उतना खास करने में नाकाम रही है। टीम इंडिया ने साल 2021 में एक ऐसा कीर्तिमान बनाया था, जिसे तोड़ने का प्रयास इंग्लिश टीम करेगी। दोनों देशों के बीच खेले गए टी20 मैचों में भारत के नाम पारी में टॉप स्कोर का कीर्तिमान दर्ज है। इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में यह रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर सकती है। हालांकि टीम इंडिया के पास भी अपना कीर्तिमान तोड़ते हुए एक नया इतिहास रचने का मौका रहेगा। साल 2021 में टीम इंडिया ने अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट पर 224 रनों का स्कोर खड़ा किया था। यह अब तक टॉप स्कोर है। इंग्लैंड की टीम इस कीर्तिमान को तोड़ना चाहेगी, हालांकि भारतीय सरजमीं पर ऐसे कीर्तिमान तोड़ पाना आसान कार्य तो नहीं होता है। उस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने धमाकेदार अंदाज में अर्धशतक जड़े थे। ये दोनों ओपन करने के लिए आए थे और पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े थे। इंग्लैंड को इस मैच में 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड के लिए जोस बटलर अरु डेविड मलान ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 170 चढ़ा; निफ्टी 23,200 के करीब बंद

नईदिल्ली। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सात महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करने के बाद घरेलू शेयर बाजार मंगलवार (14 जनवरी) को हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि, आईटी स्टॉक्स में गिरावट ने बाजारों में तेजी को सीमित कर दिया। इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1.4% गिरकर बंद हुए थे। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मंगलवार (14 जनवरी) को मामूली बढ़त के साथ 76,335 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 500 अंक तक चढ़ गया था। अंत में सेंसेक्स 169 अंक या 0.22% चढ़कर 76,499.63 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी मजबूती के साथ ओपन हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 23,200 के पार तक चला गया था। अंत में यह 90.10 अंक या 0.39% की बढ़त लेकर 23,176.05 पर क्लोज हुआ।

हल्दी किसानों की 40 साल पुरानी मांग पूरी

नईदिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद जिले में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन किया। यह बोर्ड हल्दी किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, जो लंबे समय से इसे लेकर इंतजार कर रहे थे। पियूष गोयल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बोर्ड का उद्घाटन किया और इसे संक्रांति के शुभ अवसर पर लॉन्च करने की बात कही। गोयल ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्दी की उत्पादकता बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं और बोर्ड इन क्षेत्रों में विकास के लिए काम करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दशक में निजामाबाद हल्दी का औसत दाम लगभग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन 2024 में यह दाम बढ़कर 18,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, और यह ट्रेंड अभी भी जारी है।

थोक महंगाई दर दिसंबर 2024 में बढ़कर 2.37 प्रतिशत रही

नईदिल्ली। भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में बढ़कर 2.37% हो गई, जो नवंबर में 1.89% थी। खाद्य पदार्थों, कपड़ा और अन्य विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। मंगलवार को सरकार ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। खाद्य और कपड़ों की कीमतों में माह-दर-माह आधार पर वृद्धि हुई। समग्र थोक मूल्य सूचकांक में नवंबर की तुलना में 0.38% की गिरावट आई थी। प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी का सूचकांक, जिसकी डब्ल्यूपीआई में 22.62% भागीदारी है, मासिक आधार पर 2.07% गिरा। इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 3.08% नरमी आई और कच्चे पेट्रोलियम व्र प्राकृतिक गैस के भाव में भी 2.87% की गिरावट दर्ज की गई। गैर-खाद्य वस्तुओं में 2.53% की वृद्धि हुई, जबकि खनिज कीमतों में 0.48% का इजाफा हुआ। ईंधन और बिजली खंड, जिसका भार 13.15% है, में दिसंबर में 1.90% की वृद्धि दर्ज की गई।

लक्ष्मी डेंटल आईपीओ में 15 तक अप्लाई करने का मौका

नईदिल्ली। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग पर निवेशकों को अच्छा मुनाफे का इशारा दे रहा है। आईपीओ अप्लाई करने के लिए सोमवार (13 जनवरी) को खुल गया। इच्छुक निवेशक 15 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी का लक्ष्य अपने आईपीओ के जरिये 698 करोड़ रुपये जुटाना है। इसके लिए कंपनी ने 407-428 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ब्रोकरेज ने लक्ष्मी डेंटल आईपीओ को लॉन्ग टर्म लिहाज से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। लक्ष्मी डेंटल आईपीओ को इन्वेस्टर्स से स्ट्रांग रिस्पांस मिला रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड रिटेल और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की तरफ से देखी जा रही है। पब्लिक इश्यू को पहले ही दिन पांच गुना से ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया गया था।

2025-26 के बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों को देनी होगी राहत

प्रह्लाद सबनानी

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मध्यमवर्गीय परिवारों की प्रमुख भूमिका रहती है। देश में ही निर्मित होने वाले विभिन्न उत्पादों की मांग इन्हीं परिवारों के माध्यम से निर्मित होती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार जब मध्यमवर्गीय परिवारों की श्रेणी में शामिल होते हैं तो उन्हें नया स्कूटर, नया फ्रिज, नया एयर कंडिशनर, नया टीवी एवं इसी प्रकार के कई नए पदार्थों (उत्पादों) की आवश्यकता महसूस होती है। साथ ही, नए मकानों की मांग भी मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच से ही निर्मित होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जिस देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ती है उस देश का आर्थिक विकास भी उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ता है। भारत में भी हाल ही के वर्षों में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। परंतु, मुद्रा स्फीति, कर का बोझ एवं इन परिवारों की आय में वृद्धि दर में आ रही कमी के चलते इन परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे कई कम्पनियों का यह आंकलन सामने आया है कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं (Fast Moving Consumer Goods - FMCG) के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली कम्पनियों का इस संदर्भ में आंकलन बेहद चौंकाने वाला है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही में इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री एवं लाभप्रदता में भी कमी दिखाई दी है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार एवं

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सहायता योजनाओं का लाभ अब सीधे ही इन परिवारों को पहुंचने लगा है। 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रतिमाह मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों के खातों में सहायता राशि सीधे ही जमा की जा रही है। विभिन्न राज्यों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहिना योजना आदि माध्यम से महिलाओं के खातों में सीधे ही राशि जमा की जा रही है। इसके साथ ही इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होने लगे हैं। जिससे इस श्रेणी के परिवारों में से कई परिवार अब मध्यमवर्गीय श्रेणी के परिवारों में शामिल हो रहे हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्री ने हाल ही में भारतीय संसद को बताया है कि देश में पिछले 10 वर्षों में रोजगार उपलब्ध नागरिकों की संख्या 36 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 64.33 करोड़ के स्तर पर आ गई है, यह संख्या वर्ष 2014-15 में 47.15 करोड़ के स्तर पर थी। वर्ष 2024 से वर्ष 2014 के बीच, 10 वर्षों में रोजगार में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी अर्थात इस दौरान केवल 2.9 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित हो सकीं थी, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच 17.19 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई हैं, यह लगभग 6 गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। पिछले केवल एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच ही देश में लगभग 4.6 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच रोजगार में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच कृषि के क्षेत्र में रोजगार में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई हैं। इसी प्रकार विनिर्माण के क्षेत्र में भी वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच रोजगार में केवल 6 प्रतिशत दर्ज हुई थी जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। सेवा के क्षेत्र में तो और भी अधिक तेज वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच सेवा के क्षेत्र में रोजगार 25 प्रतिशत की दर से बढ़ा था, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस सबका असर बेरोजगारी की दर में कमी के रूप में देखने में आया है। देश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2017-18 के 6 प्रतिशत से वर्ष 2023-24 में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है।

तीन दिवसीय तातापानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं: सीएम साय

रायपुर। प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के कण-कण में बसे हुए हैं, जन-जन में बसे हुए हैं। भगवान श्रीराम हमारे भांचा राम हैं। पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, जहां भांजे को भगवान स्वरूप में पूजते हैं, उनका चरण पखारते हैं। उन्हें दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। हमारी सरकार की श्रीराम लला दर्शन योजना से राज्य के 20 हजार से अधिक लोग अयोध्या में भगवान श्रीराम का दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तीन दिवसीय तातापानी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उक्त बातें कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम लोग तातापानी संक्रांति परब में हर साल यहां आते हैं। पिछले साल जब हम लोग यहां आए थे, तब इस पावन स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। परिणाम आप सबके

सामने है, आज तस्वीर बहुत कुछ बदली-बदली सी नजर आ रही है। यहां विकास के काम तेजी से हुए हैं और लगातार हो ही रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। खासकर सरगुजा और बस्तर जिले में अनेक ऐसे सुंदर स्थान हैं, जो पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। ऐसे स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन स्थलों का विकास तेजी से कराया जा रहा है। तातापानी भी ऐसी ही जगहों में से एक है। हम इन सभी दर्शनीय स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेंगे। इससे रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने 177 करोड़ रुपये के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया है। इनमें करीब 134 करोड़ रुपये की लागत के 140 कार्यों का भूमिपूजन और 43 करोड़ रुपये के 58 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा परिसर के निर्माण के लिए हम लोगों ने आज भूमिपूजन किया है, जिसके निर्माण से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बलरामपुर कॉलेज में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 300 बेटियों के हाथ पीले हुए हैं। उन्होंने सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए सभी के सुखमय गृहस्थ जीवन की मंगल कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तातापानी संक्रांति परब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का गौरव है। तातापानी दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है, जहां गर्म-पानी के कुंड के रूप में प्रकृति की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तातापानी संक्रांति परब का यह आयोजन समाज में एकता और सौहार्द का संदेश भी देता है। इस महोत्सव में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ ही पतंगबाजी और आरागाही हवाई पट्टी पर पैरासेलिंग का आनंद भी आप लोग उठा पाएंगे। यहां किसान संगोष्ठी और पंच-सरपंच सम्मेलन भी होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य सामने रखा है। इसी के अनुरूप हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया है। इस साल छत्तीसगढ़ में धान की फसल अच्छी हुई है। 3100 रुपए क्विंटल के दाम से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी हो रही है। इस साल किसान भाइयों के घरों में रिकॉर्ड पैसा आने वाला है। अभी किसान भाइयों को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा है।

तेज़ी से विकसित हो रहा है छत्तीसगढ़ : कश्यप

देवपहरी में 81 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का शिलान्यास-भूमिपूजन

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं।

सभी वर्गों के शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सेवाओं में बढ़ोत्तरी के साथ ही कला-संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वनमंत्री कश्यप आज कोरबा जिले के ग्राम देवपहरी में आयोजित शिलान्यास और भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां 81 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमिपूजन किया।

वनमंत्री केदार कश्यप ग्राम देवपहरी में गौ-मुखी सेवाधाम द्वारा आयोजित तिल-लाडू ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि

गौ-मुखी सेवा धाम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कल्याण का कार्य कर रही है।

उन्हें शिक्षा से जोड़कर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और संस्कृति को जोड़ते हुए समाज के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने रस्साकशी, कबड्डी, तीरंदाजी के विजेताओं का सम्मान कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया मंत्री कश्यप ने देवपहरी में वन विभाग अंतर्गत 5 करोड़ 89 लाख रूपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया।

2018 से 2023 तक पीएससी की सभी भर्ती रद्द करने की मांग

पूर्व सीएम की बेटी के चयन की भी जांच की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच के बीच कांग्रेस सरकार में हुई सभी भर्ती को रद्द करने की मांग उठने लगी है। भाजपा के युवा नेता उज्जवल दीपक ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर राज्य के युवाओं को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी की पीएससी के जरिये हुए चयन की भी जांच की मांग की।

उज्जवल दीपक ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के अनुसार [redacted] धांधली की [redacted] जांच चालू होने के बाद कई घोटालेबाजों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कांग्रेस शासनकाल में राज्य के युवाओं को [redacted] / व्यापम के अधिकारियों द्वारा संगठित अपराध स्तर की कार्यप्रणाली के माध्यम से धोखा दिया गया है और सभी तथ्य यह संकेत दे रहे हैं कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में अधिकारियों- राजनेताओं के बच्चों के चयन हेतु धांधली की गई है।

उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चार मांग की इनमें-

1. राज्य में साल 2018 से 2023 तक समस्त परीक्षाओं एवं सरकारी भर्तियों की सीबीआई जांच हो.
2. पीएससी 2021-2022 के परिणाम रद्द हों. समस्त नियुक्तियां रद्द की जाएँ।
3. सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, भ्रष्टाचार से चयनित अधिकारियों का नार्को परीक्षण।
4. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पुत्री का सहायक प्राध्यापक - वाणिज्य (उ.शि.वि) परीक्षा -2019 में चयन की जांच।

उज्जवल दीपक ने कहा कि अभी जो सीबीआई जांच चल रही है, उसका दायरा बढ़ाकर सभी परीक्षाओं और भर्तियों को इस जांच में शामिल किया जा सकता है। साल 2024 में आयोजित पीएससी परीक्षा की पारदर्शिता से युवा अभ्यर्थी आशान्वित हैं और आपके सुशासन से उनमें हर्ष व्याप्त है। इसी दिशा में आपसे सनम्र निवेदन है की लोक सेवा आयोग / व्यापम सहित समस्त सरकारी परीक्षाओं और भर्तियों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को आपके शासनकाल में पुनर्स्थापित किया जाए।

डिप्टी सीएम साव ने मिशन अमृत के तहत योजना का किया औचक निरीक्षण

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत पहुंचकर मिशन अमृत 2.0 के तहत निर्माणाधीन जल प्रदाय योजना के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सरगी नाला एनीकट पर प्रगतिरत इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने दरीपार रोड किनारे निर्माणाधीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर निर्माणाधीन पंप हाउस, फिल्टर टैंक, रिजर्वायर टैंक इत्यादि का बारिकी से निरीक्षण किया। राजिम के विधायक रोहित साहू, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और गरियाबंद के कलेक्टर दीपक अग्रवाल भी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे उप मुख्यमंत्रीअरुण साव ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्माण कार्यों तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों की सुविधा और मजबूती को ध्यान में रखते हुए अच्छी सामग्रियों का उपयोग करने को कहा।

निःशुल्क नेत्र शिविर के लिए डॉ. दिनेश मिश्र का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में

रायपुर। विगत 33 वर्षों से हर वर्ष दीपावली एवं होली त्यौहारों के समय निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन अपने नयापारा, फूल चौक, रायपुर स्थित अस्पताल में लगातार करने को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने आप में अद्वितीय जनसेवा का कार्य मानते हुए इस कार्य के लिए प्रसिद्ध वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. दिनेश मिश्र को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस रिकॉर्ड के लिए डॉ. दिनेश मिश्र को संस्था द्वारा जारी पदक व प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था की छत्तीसगढ़ हेड श्रीमती सोनल राजेश शर्मा तथा विधानसभा अध्यक्ष के सचिव श्री विक्रम सिसोदिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि डॉ. दिनेश मिश्र द्वारा काफी लंबे समय से समाजसेवा का कार्य किया जा रहा है। निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों के अलावा अंधविश्वास उन्मूलन और टोनही प्रताड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए उनके द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किए गए हैं। संस्था की छत्तीसगढ़ प्रमुख श्रीमती शर्मा ने कहा कि डॉ. दिनेश मिश्र ने पिछले 33 वर्षों में हर वर्ष दीपावली व होली में निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किए। यह 66 शिविर एक तरह से बहुत ही आवश्यकता और आपातकालीन परिस्थितियों में किए गए जब बड़े-बड़े त्यौहारों के कारण चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मरीज और उनके रिश्तेदार दुर्घटनाग्रस्त हालत में भटकते हैं। डॉ. मिश्र ने अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से विश्वसनीय मदद प्रदान करते हुए मानवता की बड़ी सेवा की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने डॉ. दिनेश मिश्र को पदक, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया एवं उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1991 में यह सेवा शुरू की थी। उन्होंने देखा था कि त्यौहारों की खुशियों को गम में बदलने से बहुत ही निराशा का माहौल बनता है। ऐसे में शहर के बीच ऐसे निःशुल्क शिविर लगाने की जरूरत थी जहां आपात स्थिति के नाम पर बेहद जरूरतमंद और आपात स्थिति में पहुंचे मरीजों के साथ किसी भी तरह की उपेक्षा या धोखाधड़ी न हो।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

पिछड़ा वर्ग को चुनाव लड़ने से रोकने षड्यंत्र किया: बैज

रायपुर। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 15 जनवरी को एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर प्रदेश में वर्ग संघर्ष फैलाने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती करने का षड्यंत्र किया ताकि प्रदेश की

बहुसंख्यक आबादी चुनाव लड़ने से वंचित रह जाये। पहले तो कहा गया पिछड़ा वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा, जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित नहीं हुआ। भाजपाई बेशर्मीपूर्वक कहते है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो भाजपा के नेता और सरकार ही बता दे उनके नये आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिये क्या व्यवस्था हुई है? पिछड़ा वर्ग का पंचायतों में आरक्षण कम क्यों हो गया? एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद में पिछड़ा वर्ग के लिये क्यों आरक्षण नहीं हुआ? भाजपा प्रदेश के आरक्षित वर्ग में वर्ग संघर्ष करवाने यह षड्यंत्र रचा है। बस्तर और सरगुजा संभाग में आरक्षित वर्ग को बड़ा नुकसान है।

आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्री लखन लाल देवांगन फ्लोरा मेक्स कंपनी से अपने संबंधों के बारे में प्रदेश की जनता को स्पष्टीकरण दें। वे कंपनी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होने दे रहे? पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के बीच में वे रोड़ा क्यों बन रहे है? महिलाओं को न्याय दिलाने के बजाय

अब अपनी गलतियों का ठीकरा विपक्ष पर ठोकने की कोशिश बंद करे। फ्लोरा मैक्स कंपनी की पीड़ित महिलाएं मंत्री लखन लाल देवांगन के ऊपर कंपनी को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। कंपनी के खिलाफ महिलाओं द्वारा किये जाने वाले आंदोलन से मंत्री लखन लाल देवांगन की तिलमिलाहट बताती है कि वे कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने के कारण महिलाओं को धमका रहे थे। फ्लोरा मैक्स कंपनी की पीड़ित महिलाओं से अभद्रता के मामले में महिलाओं से माफी मांगे। विपक्ष पर आरोप लगाकर मंत्री अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। फ्लोरा मेक्स कंपनी के खिलाफ कार्यवाही किसके दबाव पर नहीं हो रही, महिलाओं पर गलत एफआईआर किसके दबाव में हुआ? सरकार फ्लोरा मैक्स कंपनी के जालसाजी की जांच सीबीआई से कराने का साहस क्यों नहीं दिखा रही? भाजपा की सरकार को बने 1 साल पूरा हो गया।

सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में विफल: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार कैसा युवा उत्सव मना रही है युवा उत्सव में शामिल युवाओं के चेहरा में बेरोजगारी के चलते तनाव और मायूसी दिख रहा है भविष्य को लेकर युवा चिंतित है। युवाओं को लगा की युवा उत्सव के मंच के माध्यम से भाजपा की सरकार एक लाख सरकारी नौकरी भर्ती शुरू

करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ युवा उत्सव के दिन प्रदेश के बीएडधारी शिक्षक नौकरी जाने से नाराज सड़कों पर नौकरी देने की मांग को लेकर दंडवत प्रणाम कर रहे थे आंदोलन कर रहे हैं और अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उन युवाओं की बात सुन नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद युवाओं में हताशा और निराशा देखी गई है युवा रोजगार ढूंढ रहे और सरकार नौकरी में लगे लोगों को बेरोजगार कर रही है। हैदराबाद की निजी इवेंट कंपनी के माध्यम से भाजपा सरकार पुलिस आरक्षक और वन रक्षकों के पदों को बेचने का काम कर रही है। विद्या मितान, अतिथि शिक्षा नौकरी से निकाल दिये गये। 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा था, लेकिन 13 महिनों से छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी लगातार नौकरी से निकाले जा रहे है।

चिटफंड पार्ट 2 हजारों करोड़ की लूट सरकार मौन: महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रामेन डेका को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रदेश की हजारो गरीब महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगारो से करोड़ो रूपये की धोखाधड़ी की राशि वापस करने एवं निवेश के नाम पर बैंको से दिलवाए गए ऋ़ण को माफ करने के संबंध में पत्र

लिखा है। भाजपा राज में यह चिटफंड पार्ट 2 है, भाजपा की पिछली सरकार में भी प्रदेश के आम गरीब जनों के करोड़ों रुपए चिट फंड के नाम पर लूट गए थे जिसे कांग्रेस की सरकार ने कुछ हद तक गरीबो के रूपये लौटने का कार्य किया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के बैंकों से लोन दिलाने और दिए गए ऋ़ण की राशि को अपनी कम्पनियों में निवेश करवाने के नाम पर प्रदेश के कोरबा, जांजगीर, बालोद समेत छत्तीसगढ़ के 10-12 जिलो की लगभग 40 हजार महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों से हजारों करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कोरबा की फ्लोरामेक्स कम्पनी और बालोद की सहत्रषि संस्थान सहित सैकड़ो गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा महिलाओं को भरोसा भी दिलाया गया था।

अनारक्षित सीट पर बीजेपी खैरात बांटना चाहती है: भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गरमा गई है। पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण को लेकर बीजेपी की प्रेसवार्ता के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ओबीसी के लिए इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता. सरकार ने अधिकार

छीन ली और अब कह रहे कि अनारक्षित सीट से टिकट देंगे. बीजेपी खैरात बांटने जैसी बात कर रही है. कोई भी अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकता है. इससे साफ होता है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है. मंत्री लखनलाल देवांगन के वायरल वीडियो पर भूपेश बघेल ने कहा, ये कहते थे महिलाओं ने इन्हें जिताया है. अब उन्हीं महिलाओं को ये उठाकर फेंकने की बात कह रहे हैं. इनमें अहंकार आ गया है. अपने आपको अवतारी समझने लगे हैं. भ्रम हो गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा. सीजीपीएससी घोटाला मामले में लाइन ऑफ एक्शन में बदलाव को लेकर कहा, सरकार में आने से पहले बीजेपी ये घोषणा की थी इसलिए ये किसी भी स्तर तक जा रहे. लोहारीडीह हिंसा मामले में भी दर्जनों गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में लोगों को रिहा किया गया था. पीएससी मामले में जिन 15 बच्चों की नियुक्ति रोकी गई।

मुख्य सूचना आयुक्त के लिए मुख्य सचिव समेत 58 दावेदार...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके लिए 58 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें वर्तमान आईएएस, आईपीएस समेत रिटायर आईएएस, आईपीएस, मीडिया के लोग भी शामिल हैं।

अभी तक इस पद के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन के आवेदन की खबर आई थी। मगर एनपीजी न्यूज को पता चला है कि डीजीपी अशोक जुनेजा, रिटायर मुख्य सचिव आरपी मंडल, रिटायर डीजीपी डीएम अवस्थी, रिटायर राजस्व बोर्ड के प्रभारी चेयरमैन उमेश अग्रवाल, बिलासपुर, रायपुर के रिटायर कमिश्नर डॉ० संजय अलंग ने भी मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए अपना आवेदन भरा है।

हालांकि, यह पहला मौका है जब सीआईसी के एक पद के लिए इतने बड़े और पावरफुल लोगों ने अप्लाई किया है। पहले इस पद के लिए आवेदन नहीं मंगाया जाता था। अशोक विजयवर्गीय और सरजियस मिंज को बिना आवेदन के सीआईसी बनाया गया था।

मगर रायपुर के पर्यावरणविद नीतिन सिंघवी ने इसे आरटीआई में जानकारी मांगकर चुनौती दी थी कि बिना आवेदन मंगाए

सीआईसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसके बाद रमन सरकार ने पहली बार रिटायर एसीएस एमके राउत समेत अन्य सूचना आयुक्तों के लिए आवेदन मंगाकर नियुक्ति दी थी।

मगर इतनी बड़ी संख्या में इस पद के लिए कभी भी आवेदन नहीं आए। दरअसल, मुख्य सूचना आयुक्त टॉप के रिटायर अफसर को ही बनाया जाता है। इसलिए, इस पद के लिए गिने-चुने ही आवेदन आते हैं। सूचना आयुक्त के लिए जरूर आवेदनों की संख्या ज्यादा होती है।

बहरहाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन के सीआईसी पद के लिए दावेदारी की खबर आई थी तो लगा था कि ऐसे पदों के लिए बिना सरकार की सहमति के लिए आवेदन नहीं किया जाता। ऐसे में, उनका सीआईसी बनना लगभग तय माना जा रहा था। मगर इस बार इतने बड़े-बड़े लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पशोपेश में पड़ जाएंगे कि किसे सलेक्ट करें... किसे दुखी। कह सकते हैं कि अब मुख्य सूचना आयुक्त के लिए तगड़ा कंपीटिशन हो जाएगा। नक्सल मोर्चे पर कामयाबी के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा का और बढ़ा हुआ है। फिर आरपी मंडल और डीएम अवस्थी जैसे सीएस और डीजी पुलिस के पद से रिटायर अफसर बिना किसी जैक और उम्मीद के आवेदन नहीं किए होंगे।

बता दें, मुख्य सूचना आयुक्त का सलेक्शन तीन सदस्यीय कमेटी करती है। इनमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होता है। याने होता वही है, जो सरकार चाहती है।

एकाग्रता के साथ कठिन परिश्रम से मिलती है मंजिल: नेताम

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि एकाग्रता के साथ कठिन परिश्रम से मंजिल को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी के साथ अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के निर्माण का सपना जुड़ा होता है। विद्यार्थियों को भी अपने माता-पिता तथा रिश्ते-नातेदारों के सपने को साकार करने के लिए एकाग्र मन से अर्जुन की भांति केवल चिड़िया के नेत्र को केन्द्र में रखते हुए अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में राज्य सरकार भी हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। उक्त

बातें आज राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने आज लगभग 34 लाख रूपए की लागत से निर्मित 40 सीटर आधुनिक कम्प्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री नेताम ने नववर्ष की सौगात के रूप में वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंग्लिश डिक्शनरी प्रदान की और बच्चों से चर्चा का उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली। मंत्री नेताम ने कहा कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा लेकर औरों को भी रोजगार देने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आवासीय विद्यालयों में सरकार शैक्षणिक वातावरण के साथ-साथ बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे है। यहां रहने वाले विद्यार्थी हजारों बच्चों में चयन करके शिक्षा के लिए यहां लाया जाता है। विद्यार्थियों को भी अपने मंजिल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.